



## जशापुर में नहीं हुआ कोई प्लेन क्रेस, जंगल की आग से फैली अफवाह

रायपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के जशापुर में कथित प्लेन क्रेस की खबर पूरी तरह अफवाह साबित हुई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विमान हादसा नहीं हुआ। जंगल में लगी आग से उड़ते धुएं के कारण ग्रामीणों को भ्रम हुआ होगा और गलत सूचना दे दी गई। जिले के कलेक्टर रोहित व्यास और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेश सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच की। अधिकारियों को घटनास्थल पर विमान का कोई मलबा नहीं मिला, जिसके बाद इस खबर को पूरी तरह खारिज कर दिया गया। प्रशासन के अनुसार, इलाके में जंगल में लगी आग से उड़ते धुएं को देखकर ग्रामीणों ने इसे विमान दुर्घटना समझ लिया। देखते ही देखते यह सूचना सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई और अफवाह का रूप ले लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने झारखंड और ओडिशा के एयर ट्राॅफिक कंट्रोल से भी संपर्क किया। दोनों ही जगहों से पुष्टि हुई कि उस समय किसी भी विमान का संपर्क नहीं टूटा था और न ही कोई विमान उस क्षेत्र में लापता हुआ। बताया गया कि जशापुर के चारभाठी क्षेत्र में एक चार्टर्ड प्लेन उड़ता देखा गया था। इसके कुछ समय बाद हादसा से धुआं उड़ता नजर आया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि के ऐसी खबरों पर विश्वास न करें और अफवाह फैलाने से बचें। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की भ्रामक सूचनाएं न केवल प्रशासनिक संसाधनों पर दबाव डालती हैं, बल्कि अनावश्यक दहशत भी पैदा करती हैं।

## बीजेपी विधायक के बेटे की करतूत के बाद उनके बयान पर बढ़ा विवाद

-थार से टक्कर मारकर पांच लोगों को किया था घायल

शिवपुरी (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा क्षेत्र में 16 अप्रैल को हुए सड़क हादसे को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक तनाव बढ़ गया है। इस मामले में आरोप है कि एक थार वाहन से टक्कर में पांच लोग घायल हुए, जिसके बाद स्थानीय राजनीति में हलवल तेज हो गई। घटना के बाद बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का बयान और उनका रुख लगातार चर्चा में है। शुरुआती प्रतिक्रिया में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि एक जनप्रतिनिधि के लिए जनता सर्वोपरि होती है और पीड़ितों को न्याय दिलाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। हालांकि, कुछ दिनों बाद उनके बयानों और पुलिस अधिकारियों के प्रति उनकी भाषा को लेकर विवाद और बढ़ गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, विधायक ने करेरा के एसडीओ आर्युष जाखर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि अधिकारी उन्हें क्षेत्र में आने से रोकने की बात कर रहा है, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई और तीखे शब्दों में प्रतिक्रिया दी। इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। इस बीच उनके बेटे से जुड़े विवाद का भी उल्लेख सामने आया है, जिसमें आरोप है कि वह बिना नंबर प्लेट और कथित रूप से संशोधित थार वाहन के साथ थाने पहुंचे थे। इस घटना ने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है। विधायक ने जांच प्रक्रिया और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ गलत तरीके से कार्रवाई या दबाव लगाया जा रहा है, जबकि पुलिस प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले की जांच जारी है। इस घटनाक्रम ने स्थानीय स्तर पर सत्ता और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। विपक्षी दल इसे लेकर सरकार और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि प्रशासन मामले की निष्पक्ष जांच की बात कर रहा है।

## पहलगाव हमले की पहली बरसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के पहलगाव में हुए आतंकी हमले की पहली बरसी से पहले पूरी कश्मीर घाटी के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। सेना के अधिकारियों के अनुसार 22 अप्रैल को होने वाली बरसी के मद्देनजर सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि 22 अप्रैल 2025 को वैसरन मैदान में हुए आतंकीवादी हमले में 26 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसमें अधिकतर पर्यटक शामिल थे। यह हमला लश्कर-ए-तैबा के आतंकियों द्वारा किया गया था। सेना के अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल 22 अप्रैल को लश्कर-ए-तैबा के आतंकीवादियों ने पहलगाव में 26 लोगों को मार गिराया था। इस आतंकी हमले की पहली बरसी से पहले कश्मीर भर के दूरिस्ट रिजॉर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा एजेंसियों को पहलगाव आतंकी हमले की बरसी से एक दिन पहले, खासकर दूरिस्ट जगहों के आसपास किसी भी संभावित विस्फोट गतिविधि के लिए अलर्ट रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि एक फुलपूफ सुरक्षा प्लान बनाने के लिए ग्राउंड लेवल पर तैयारी मॉडिट की गई, जबकि सीनियर अधिकारियों ने हाल ही में इन इंतजामों का रिव्यू किया। अब, करीब एक साल बाद, पहलगाव के मशहूर मैदान फिर दूरिस्ट की पहल-पहल से गुलजार है, और किसी को भी अंततःनाम जिले में मिनी रिजॉर्ट जरूर दे जाने का फैसला नहीं है, जो पिछले साल के आतंकी हमले के साप से उबर रहा है। दूरिस्ट की सुरक्षा पकड़ा करने के लिए पहलगाव रिजॉर्ट में कई नए उपाय शुरू किए गए हैं। इसमें सर्विस प्रोवाइडर और वेंडर, जिसमें पानीवाला भी शामिल है, का विजिटर से बात करने से पहले पहले का वैरिफिकेशन किया जा रहा है। पहलगाव में दूरिस्ट की सुरक्षा के लिए सभी दूरिस्ट सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक खास क्वॉरान्टेन कोड-बेस्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम शुरू किया गया है।

## केरल में निजी संपत्ति विवाद बन गया राजनैतिक अखाड़ा... भाजपा और माकपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े

नेट्टयाम (एजेंसी)। केरल के नेट्टयाम में दो रिश्तेदारों के बीच शुरुआ हुआ निजी संपत्ति विवाद देखते ही देखते राजनीतिक जंग में बदल गया। घटना में भाजपा और माकपा (सीपीआईएम) के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हिंसा हुई, जिसमें बीच-बचाव करने पहुंचे तीन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामले में कड़ा रुख दिखाकर दोनों पार्टियों के कुल 94 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस जांच के अनुसार, इस पूरे बवाल की शुरुआत नेट्टयाम के मलमूकल इलाका निवासी की रिश्तेदारों के बीच जमीन को लेकर हुए विवाद से हुई। इनमें से एक पक्ष भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से जुड़ा है। दूसरा पक्ष मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) का समर्थक है।

# ओसीआई में ढील और मछुआरों की रिहाई से भारत-श्रीलंका रिश्तों में आई मजबूती

-उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के दौर के दौरान हुई अहम घोषणाएं, प्रवासी भारतीयों को राहत और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को नई दिशा देने के उद्देश्य से उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के हालिया दौर के दौरान कई महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम उठाए गए हैं। इस दौर को दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने जानकारी दी कि भारत सरकार ने ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब श्रीलंका में बसे प्रवासी भारतीयों की पांचवीं और छठी पीढ़ी को भी ओसीआई कार्ड के लिए पात्र माना जाएगा। पहले यह सुविधा केवल चौथी पीढ़ी तक सीमित थी। इस बदलाव से हजारों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है और भारतीय मूल के लोगों का अपने देश से जुड़ाव और मजबूत होगा।

इसके साथ ही ओसीआई कार्ड के लिए



आवश्यक दस्तावेजों को लेकर भी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब श्रीलंका सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पुराने भारत-श्रीलंका पासपोर्ट और

कोलंबो तथा कैंडी स्थित भारतीय मिशन के रिकॉर्ड को भी मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इससे आवेदन प्रक्रिया अधिक सुगम और

पारदर्शी होने की संभावना है। दौर के दौरान भारत ने श्रीलंका सरकार का आभार भी व्यक्त किया। उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके को हाल ही में भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिए धन्यवाद दिया। जानकारी के अनुसार, बीते कुछ हफ्तों में 47 भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया है, जिन्हें जल्द ही भारत वापस लाया जाएगा।

मछुआरों के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से संवेदनशीलता बनी रही है। ऐसे में हालिया रिहाई को सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भी माना कि इस समस्या का स्थायी समाधान दोनों देशों के संयुक्त प्रयासों से ही संभव है। विशेषज्ञों का मानना है कि ओसीआई नियमों में ढील और मानवीय मुद्दों पर सहयोग, दोनों ही कदम भारत-श्रीलंका संबंधों में नई ऊर्जा भरने वाले हैं। यह दौर न केवल प्रवासी भारतीयों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि क्षेत्रीय कूटनीति में भारत की सक्रिय भूमिका को भी दर्शाता है।

## हरियाणा से अखिलेश यादव ने दिया बड़ा सियासी संदेश, 2027 में सरकार बनाने का दावा

-कहना- बीजेपी की राजनीति और रणनीति फूट डालो और राज करो वाली



नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक सर्गामी तेज हो गई है। इस बीच अखिलेश यादव ने हरियाणा के रेवाड़ी से बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए दावा किया कि उनकी पार्टी आगामी चुनावों के बाद सत्ता में वापसी करेगी।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रेवाड़ी पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट रहेगा और कांग्रेस उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने सीट बंटवारे के सवाल पर कहा कि उनके लिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि महिला आरक्षण के नाम पर सत्ताधारी पार्टी राजनीति कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी महिला मतदाताओं के बीच भी विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि, उनका मानना है कि महिलाएं अब पहले से अधिक जागरूक हैं और महंगाई, सामाजिक दबाव और शोषण जैसे मुद्दों पर अपनी राय स्पष्ट रूप से व्यक्त करेंगी। अखिलेश यादव के इन बयानों को आगामी चुनावों की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

## महिला आरक्षण विधेयक पर सियासत तेज, कांग्रेस ने कहा- सरकार डैमेज कंट्रोल में लगी

-परिशीलन को लेकर उठाए सवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित हो जाने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस ने सरकार द्वारा जारी किए गए 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' (फेक) पर तीखा हमला बोला है और इसे 'डैमेज कंट्रोल' की कोशिश कर दिया है।

कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने यह फेक विधेयक पेश करने से पहले जारी नहीं किया, बल्कि संसद में असफलता मिलने के बाद इसे सामने लाया गया, जिससे उसकी मंशा पर सवाल उठते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बयान जारी करते हुए कहा कि 17 अप्रैल की रात लोकसभा में मिली -शर्मनाक हार- के बाद सरकार अब अपनी छवि बचाने में जुटी है।



उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा जारी फेक 'तथ्यात्मक रूप से गलत' और 'ध्रामक' है, जो जानकारी से भरा हुआ है। जयराम रमेश ने विशेष रूप से परिशीलन के मुद्दे पर सरकार को घेरा।

उनका कहना था कि फेक में उन महत्वपूर्ण सवालों का कोई जवाब नहीं दिया गया है, जो संसद में विपक्ष ने उठाए थे।

गौरतलब है कि सरकार ने संविधान

(131वां संशोधन) विधेयक के माध्यम से 2029 से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रारंभिक भी इसमें शामिल था। हालांकि, यह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका।

कांग्रेस का यह भी आरोप है कि फेक में यह दावा किया गया है कि आरक्षण लागू करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिशीलन जरूरी है, जो पूरी तरह -फर्जी- और -ध्रामक- है। विपक्ष लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि सरकार महिला आरक्षण के बहाने परिशीलन लागू करने की कोशिश कर रही है, जिससे राजनीतिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। इस मुद्दे पर अब राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है।

## महिला आरक्षण बिल पर योगी सरकार ने बुलाया 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रणनीति तेज कर दी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को रविवार रात कैबिनेट बाई सबूलेशन के जरिए मंजूरी दे दी। संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक के पारित न हो पाने के बाद इस मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। विपक्ष जहां विधेयक की खामियों को गिनाकर अपने विरोध को सही ठहरा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर हमलावर है और इसे चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही इस मामले में विपक्ष पर तीखा हमला बोल चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार, 30 अप्रैल को होने वाले इस विशेष सत्र में सरकार महिला आरक्षण पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी और विपक्ष के रुख को लेकर उसे घेरने की रणनीति अपनाएगी। सत्र के दौरान विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की भी चर्चा है।

## भीषण गर्मी के बीच 15 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी-बिहार में बढ़ा खतरा

-भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दी चेतावनी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। देशभर में अप्रैल की शुरुआत से ही गर्मी में तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 15 राज्यों में आंधी, बिजली और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कई इलाकों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है।

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पूर्वांचल के राज्यों में आने वाले दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। दूसरी ओर पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू चलने की चेतावनी दी गई है। नई दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री

के आसपास रह सकता है। सुबह के समय 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अगले दिन भी मौसम में खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश में हालात ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। प्रयागराज में अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री, वाराणसी में 44.2 डिग्री और बादा में 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा कई जिलों में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है।

आईएमडी ने वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर और देवरिया समेत पूर्वी यूपी के कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। बिहार में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 अप्रैल को तेज हवाओं और आंधी की संभावना है। खासकर सीमांचल क्षेत्र में सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि गर्म हवाओं के चलते हीटस्ट्रोक

का खतरा बढ़ सकता है। जबकि पहाड़ी राज्यों में भी बदलाव के संकेत हैं। हिमाचल प्रदेश में 23 अप्रैल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होने की संभावना है।

-दक्षिण भारत में मौसम सक्रिय-

दक्षिण भारत में भी मौसम सक्रिय बना हुआ है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते मौसम के इस दौर में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जहां एक ओर लू से बचाव जरूरी है, वहीं आंधी-तूफान के दौरान भी सावधानी बरतनी चाहिए।

## अगर हमारे रिजॉइंटर को रिकॉर्ड पर नहीं तो 'मिसकैरिज ऑफ जस्टिस हो जाएगा

-कोर्ट ने कहा-रिजिस्ट्री आपकी इसलिए स्वीकार नहीं होती क्योंकि आप खुद पैरवी कर रहे हैं

नई दिल्ली (एजेंसी)। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए, इसके लिए दिग्गज सीएम अरविंद केजरीवाल सोमवार को हाई कोर्ट में पेश हुए और सीबीआई के लिखित जवाब को लेकर अपना रिजॉइंटर स्वीकार करने की गुजारिश की। कोर्ट ने केजरीवाल को प्रक्रिया की याद दिलाई पर उनके जवाब को स्वीकार कर लिया है और फैसले को दो घंटे के लिए टाल दिया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल ने कहा कि आपने अनुमति दी थी मैंम की रिजॉइंटर फाइल कर दो। रिजिस्ट्री स्वीकार नहीं कर रही है। वह आदेश में नहीं आया।

आगर हमारे रिजॉइंटर को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया। 'मिसकैरिज ऑफ जस्टिस हो जाएगा। जज ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बार बार ये नहीं बोलना चाहिए कि मिसकैरिज ऑफ जस्टिस हो जाएगा, मिसकैरिज ऑफ जस्टिस हो जाएगा, मिसकैरिज ऑफ जस्टिस हो जाएगा।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल को नियमों की याद दिलाते हुए कहा कि रिजिस्ट्री आपकी याचिका इसलिए स्वीकार नहीं करती क्योंकि खुद आप अपनी पैरवी कर रहे हैं। इसलिए आपको ही पेश होना पड़ेगा। रिजिस्ट्री का एक नियम है और आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको पहले यहां से मंजूरी लेनी पड़ेगी। यह कोई

असाधारण मामला नहीं है। हमने आपको लिखित जवाब की कॉपी दी। रिजॉइंटर कभी उसका फाइल नहीं होता है, जिस दिन आप कोर्ट से गए थे अनुमति लेकर गए थे। आपने कहा कि आप मेरा सम्मान करते हैं। मैं हर वादी का सम्मान करती हूँ। मैं इसे लिखित जवाब के रूप में रिकॉर्ड पर लूंगी। चूकि फैसला सुरक्षित है, मैं उसमें विचार करूंगी।

अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से दाखिल जवाब के रिजॉइंटर में कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने अटकेलों, डर फैलाने वाले बयानों और अपमानजनक आरोपों का सहारा लिया लेकिन जस्टिस शर्मा के बच्चों के सरकारी पैनल में होने को लेकर पक्षपात के आरोपों पर कुछ नहीं कहा

है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीबीआई इस मामले की सुनवाई केवल एक माननीय जज से करवाकर पूरी न्यायपालिका को बदनाम करना चाहती है। केजरीवाल ने सीबीआई के उन आरोपों का विरोध किया कि वह दबाव बनाना चाहते हैं और मामलों को लंबित रखना चाहते हैं और बदनाम करने के लिए कैपेन चला रहे हैं। उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताया है।

रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल ने अपने रिजॉइंटर में कहा है कि सीबीआई ने खुद स्वीकार किया है कि केंद्र सरकार की कानूनी व्यवस्था और जस्टिस शर्मा के परिवार के बीच सक्रिय व्यावसायिक संबंध हैं। उन्होंने कहा कि खुद सीबीआई के



मुताबिक, जस्टिस शर्मा के बच्चे पैनल में निष्क्रिय नाम नहीं है बल्कि सरकार से कानूनी काम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने सीबीआई की उन दलीलों का भी विरोध किया कि जिसमें एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल की दलीलों के आधार पर तो

सभी जज अयोग्य हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि तथ्यों पर जवाब देने के बजाय सीबीआई ने कहा कि देश के सभी जज अयोग्य हो जाएंगे यह विवाद को बढ़ाने और पूरी न्यायपालिका को घसीटने की कोशिश है।





## पाकिस्तान यूएई को शेष 1.5 अरब डॉलर का कर्ज लौटाएगा



कराची ।

पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक (स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान-एसबीपी) ने कहा है कि वह 23 अप्रैल तक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से लिए गए 3.5 अरब डॉलर के ऋण में से बचे 1.5 अरब डॉलर का भुगतान कर देगा। यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से लगभग 1.2 अरब डॉलर की संभावित किस्त मिलने की उम्मीद के बीच की गई है। एसबीपी प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान ने एक दिन पहले ही यूएई को 2 अरब डॉलर का भुगतान कर दिया था। इससे पहले सऊदी अरब को भी 3 अरब डॉलर की सहायता में से 2 अरब डॉलर वापस किए जा चुके हैं। केंद्रीय बैंक का कहना है कि इन भुगतान और अन्य धन प्रवाह के बावजूद देश का विदेशी मुद्रा भंडार स्थिर बना हुआ है। यह पाकिस्तान के अपनी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयासों को दर्शाता है।

**- सोने का भाव 1,53,000, चांदी 2,52,000 रुपए प्रति किलोग्राम**



नई दिल्ली ।

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों वायदा बाजारों में सोमवार को कारोबार की शुरुआत में सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। कीमती धातुओं के भाव दिमाग्र दबाव में रहे और खबर लिखे जाने तक उनकी कीमतों में और नरमी देखी जा रही है। मल्टी कमांडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का वायदा भाव 1,53,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी का वायदा भाव 2,52,300 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब बना हुआ है। एमसीएक्स पर सोने के जून कॉन्ट्रैक्ट ने आज 1,451 रुपये की गिरावट के साथ 1,53,158 रुपये प्रति 10 ग्राम पर शुरुआत की, जबकि इसका पिछला बंद भाव 1,54,609 रुपये था। खबर लिखे जाने तक यह कॉन्ट्रैक्ट 1,620 रुपये की और गिरावट के साथ 1,52,989 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस वर्ष सोने के वायदा भाव ने 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम का अपना सर्वोच्च स्तर छुआ था। वहीं चांदी के मई कॉन्ट्रैक्ट ने भी सोमवार को सुस्त शुरुआत की। यह 3,689 रुपये की गिरावट के साथ 2,53,453 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुला, जबकि इसका पिछला बंद भाव 2,57,142 रुपये था। खबर लिखे जाने के समय चांदी का यह कॉन्ट्रैक्ट 4,838 रुपये की भारी गिरावट के साथ 2,52,304 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस साल चांदी ने 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम का उच्चतम स्तर देखा था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दबाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी के वायदा भाव में कमजोरी का रुख बना हुआ है। कॉमेक्स पर सोना 4,811.80 डॉलर प्रति औंस पर खुला, जो इसके पिछले बंद भाव 4,879.60 डॉलर प्रति औंस से कम था। खबर लिखे जाने के समय यह 61.20 डॉलर की गिरावट के साथ 4,818.40 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। इस वर्ष सोने का अंतरराष्ट्रीय उच्चतम स्तर 5,586.20 डॉलर रहा। इसी तरह कॉमेक्स पर चांदी 80.24 डॉलर प्रति औंस पर खुली और खबर लिखे जाने तक 1.38 डॉलर की गिरावट के साथ 80.46 डॉलर प्रति औंस पर थी। चांदी ने इस साल 121.79 डॉलर का सर्वोच्च स्तर छुआ था।

## दिल्ली में वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश महंगा, माल ढुलाई पर पड़ेगा असर

हल्के और भारी वाहनों के लिए 40-50 फीसदी की बढ़ोतरी, वस्तुओं की कीमतों पर भी दिखेगा असर

नई दिल्ली ।

दिल्ली में अब व्यावसायिक वाहनों को प्रवेश के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है।

यह बढ़ोतरी 19 अप्रैल से लागू हो गई है, जिससे परिवहन और रसद लागत बढ़ने की आशंका है, जिसका सीधा असर

दे निक उपयोगी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ सकता है। नए आदेश के तहत, हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) के लिए ईसीसी 1,400 रुपये से बढ़कर लगभग 2,000 रुपये हो गया है, जबकि भारी ट्रकों के लिए यह शुल्क 2,600 रुपये से बढ़कर 4,000 रुपये निर्धारित किया गया है।

विभिन्न श्रेणियों के वाणिज्यिक वाहनों के लिए शुल्क में लगभग 40 से 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। एमसीडी ने सभी टोल प्लाजा को इन संशोधित दरों की तत्काल प्रभाव से लागू करने के

निर्देश दिए हैं। यह निर्णय भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 12 मार्च के निर्देश के अनुरूप है। न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, प्रदूषण कम करने और डीजल से चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश से हतोत्साहित कर बाहरी एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ने के लिए इन शुल्कों में वृद्धि का आह्वान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल से इन दरों को लागू करने और भविष्य में 5 फीसदी वार्षिक वृद्धि का प्रावधान करने का भी निर्देश दिया था। इस कदम

से जहां एक ओर दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर इसका सीधा प्रभाव व्यापार और उपभोक्ता पर पड़ने की आशंका है। एमसीडी टोल संग्रह को सुव्यवस्थित करने के लिए रे फिड-आधारित प्रणालियों जैसे उपाय भी कर रही है। अदालत ने नगर निगम को टोल ढांचे की समीक्षा करने, विस्तृत यातायात आकलन करने और आवश्यकता पड़ने पर टोल प्लाजा को स्थानांतरित करने के लिए एनएचएआई के साथ समन्वय करने का भी निर्देश दिया है।

## भारतीय बैंकों में 2026 की पहली छमाही में औद्योगिक ऋण वृद्धि संभवसर्वेक्षण

- स्थिर विस्तार की उम्मीद, निजी व सार्वजनिक बैंक अधिक आशावात

नई दिल्ली ।

फिक्की और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के एक संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय बैंकिंग क्षेत्र जनवरी-जून 2026 की अवधि में 9-13 प्रतिशत की औद्योगिक ऋण वृद्धि का अनुभव करने के लिए तैयार है। यह वृद्धि स्थिर और क्रमिक होगी, न कि कोई तेज उछाल।

इस विस्तार को पूंजीगत व्यय में चल रही बहाली, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती मांग से समर्थन मिलने की उम्मीद है। सर्वेक्षण के

विश्लेषण से पता चलता है कि यह औद्योगिक ऋण वृद्धि पूंजीगत व्यय में चल रही बहाली, बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय मांग में सुधार जैसे कारकों से समर्थित होगी। हालांकि, बैंकों की विभिन्न श्रेणियों में ऋण वृद्धि की उम्मीदें अलग-अलग हैं। छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी) और सहकारी बैंकों के गैर-खाद्य ऋण में अपेक्षाकृत रूढ़िवादी विस्तार की उम्मीद है, जो लगभग 7-9 प्रतिशत की ऋण वृद्धि दर्शाते हैं। यह मुख्य रूप से बड़े औद्योगिक उधारकर्ताओं के प्रति उनके सीमित जोखिम और खुदरा व एम्पएसएमई

ऋणों पर उनके मजबूत ध्यान के कारण है। इसके विपरीत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिक आत्मविश्वास प्रदर्शित करते हैं। इनमें ऋण वृद्धि लगभग 11-13 प्रतिशत और कुछ मामलों में 13 प्रतिशत से ऊपर की श्रेणियों में वृद्धि दर्शाते हैं। यह आशावाद उनकी बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता, मजबूत पूंजी बफर और कॉर्पोरेट ऋण में निरंतर गति से प्रेरित है, खासकर पूंजीगत व्यय बहाली के संकेतों के बीच। निजी बैंकों में गैर-खाद्य ऋण प्रतिक्रियाएं अधिक विविध वितरण दिखाती हैं। हालांकि अधिकशां बैंक 11 से 13

प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं, कुछ चुनिंदा निजी बैंक 13 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की उम्मीद भी कर रहे हैं। यह उनके मजबूत खुदरा पोर्टफोलियो, एम्पएसएमई की ऋण गति और कैलिब्रेटेड कॉर्पोरेट एक्सपोजर रणनीतियों को दर्शाता है। विदेशी बैंकों के लिए, वृद्धि 11 से 13 प्रतिशत के दायरे में रहने की उम्मीद है। यह वैश्विक तरलता की स्थिति, पूंजी आवंटन प्राथमिकताओं और घरेलू कॉर्पोरेट क्रेडिट बाजारों में उनकी चुनिंदा भागीदारी से समर्थित मध्यम आशावादिता की स्थिति है।

## शेयर बाजार हल्की बढ़त पर बंद

संसेक्स 26, निफ्टी 11 अंक उछला

मुंबई । भारतीय शेयर बाजार सोमवार को हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों से आज सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन बाजार में दिनभर उतार-चढ़ाव का माहौल रहा। हालांकि अंत में कुछ खरीबदारी से बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ है। आज दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई संसेक्स अंत में 26.76 अंकों की बढ़त के साथ ही 78,520.30 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 11.30

अंक उछलकर 24364.85 के स्तर पर बंद हुआ है। आज कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से भी बाजार पर विपरीत प्रभाव पड़ा और ये नीचे आया। आज संसेक्स के शेयरों में टैट, एशियन पैटर्स, एनटीपीसी और बजाज फाइनेंस के शेयरों में तेजी रही जबकि कोटक महिन्द्र बैंक, बीईएल, एचसीएल और एचडीएफसी बैंक के शेयर गिरे। आज एनएसई पर मिड और स्मॉलकैप शेयरों में गिरावट रही। इसके चलते निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.25 फीसदी तक गिरा जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100

इंडेक्स में भी 0.46 फीसदी की गिरावट रही। आज ज्यादातर इंडेक्स गिरावट के साथ ही लाल निशान पर बंद हुए। निफ्टी आईटी, मेटल, फार्मा, प्राइवेट बैंक, रियल्टी समेत कई इंडेक्स में गिरावट नजर आई जबकि निफ्टी ऑटो, मीडिया और पीएसयू बैंक के शेयर गिरे।

बाजार जानकारों के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से भी बाजार गिरा है। अमेरिका के एक ईरानी जहाज पर कब्जे के बाद से ही दोनों के बीच शांति वार्ता अधर में लटक गयी है। इससे ट ऑफ हॉर्मूज पर तनाव

बढ़ गया है। इसका असर कच्चे तेल पर भी दिखा और आज इसका भाव करीब 5 फीसदी बढ़कर 94.76 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इससे भी बाजार पर दबाव आया है। इससे पहले आज सुबह बाजार की सपाट शुरुआत हुई। हालांकि, शुरुआती सुस्ती के बाद बाजार में थोड़ी रिकवरी दर्ज की गई। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बावजूद, बैंकिंग सेक्टर में निवेशकों की खरीदारी ने बाजार को मजबूती प्रदान की। 24,391.50 पर खुला।

## यूएई की तेल व्यापार में डॉलर को छोड़कर युआन अपनाने की चेतावनी

- अमीरात ने अमेरिकी नीतियों को ठहराया जिम्मेदार

मुंबई ।

पश्चिम एशिया में गहराते तनाव और अमेरिका-ईरान संघर्ष के मद्देनजर, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने अपनी तेल व गैस बिक्री के लिए अमेरिकी डॉलर के बजाय चीनी युआन या अन्य वैकल्पिक मुद्राओं को अपनाने की चेतावनी दी है। यूएई ने इस स्थिति के लिए डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है, साथ ही संभावित डॉलर संकट से निपटने के लिए अमेरिका से डॉलर स्वैप लाइन की मांग की है। मैक्रोइकोनॉमिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि यूएई तेल व्यापार में युआन को अपनाता है, तो यह वैश्विक स्तर पर दशकों से कायम डॉलर के प्रभुत्व को गंभीर चुनौती देगा। चीन पहले ही कई देशों के साथ मुद्रा स्वैप समझौते कर चुका है, जिससे युआन का अंतरराष्ट्रीय उपयोग बढ़ रहा है। यदि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम नहीं होता, तो कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक अर्थव्यवस्था व मुद्रा बाजार पर असर तय है। गैर-डॉलर व्यापार देशों को अपने डॉलर भंडार को कर्ज चुकाने के लिए सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। इस बीच, भारत में भी डॉलर पर निर्भरता कम करने के संकेत मिल रहे हैं। हाल ही में भारतीय कंपनियों ने ईरान से तेल खरीद के लिए डॉलर की बजाय युआन में भुगतान किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और रिटेल जैसे अन्य सेक्टर भी वैकल्पिक भुगतान विकल्पों की तलाश में हैं, जो वैश्विक व्यापार में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है।



## पश्चिम एशिया संघर्ष का भारतीय बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता पर मामूली प्रभाव

तेल, गैस और एएसएमई क्षेत्र प्रभावित, लेकिन कॉर्पोरेट लचीलापन उत्साहजनक

नई दिल्ली ।

पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी दो महीने पुराने संघर्ष का भारत के प्रमुख बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता पर अब तक कोई खास असर नहीं पड़ा है। हालांकि, बैंकों ने चालू तिमाही में कुछ मामूली प्रभाव की आशंका जताई है और वे लगातार सतर्कता बरतते हुए अपने पोर्टफोलियो की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। इसके बावजूद, बैंक उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले महीनों में स्थिति में सुधार आएगा। भारत के प्रमुख बैंकों के अनुसार, भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद देश के बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता अभी भी अप्रभावित है। एचडीएफसी बैंक के एक अेधिकारी ने स्वीकार किया कि तेल, गैस और

उत्से सीधे जुड़े क्षेत्रों में कुछ हद तक व्यवधान देखा गया है, लेकिन कॉर्पोरेट क्षेत्र इस संकट से निपटने में सक्षम हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। उनके मुताबिक, वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कुछ मामूली असर दिख सकता है, लेकिन यह दीर्घकालिक नहीं होगा। दूसरी ओर, आईसीआईसीआई बैंक के एक अेधिकारी ने बताया कि पश्चिम एशिया संकट का यील्ड (प्रतिफल) और करेंसी (मुद्रा) पर तात्कालिक असर पड़ा है, जो वित्त वर्ष 2026 के अंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक सभी संकेतकों की निगरानी जारी रखेगा और आर्थिक वृद्धि तथा व्यापार मांग पर इसका प्रभाव संघर्ष की अवधि पर निर्भर करेगा। मार्च में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पश्चिम एशिया



संकट के कारण रुपये में रिकॉर्ड गिरावट के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में अपनी निगरानी बढ़ा दी थी। केंद्रीय बैंक ने बैंकों को शुद्ध औपन पोजीशन (एनओपी) को 10 करोड़ डॉलर तक सीमित कर दिया था। इस पोजीशन को कम करने से वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में कुछ नुकसान हुआ और 10 अप्रैल तक अनवाइंड करने की समय-सीमा के कारण इसका एक हिस्सा वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में भी दिखेगा। हालांकि, बैंक कुल मिलाकर मजबूत स्थिति में बने हुए हैं।

## क्रिप्टोकॉइन्स बाजार में फिर गिरावट, बिटकॉइन-एथेरियम टूटे

क्रिप्टोकॉइन्स जीनियस टर्मिनल ने निवेशकों को 200 फीसदी से अधिक का रिटर्न दिया

नई दिल्ली ।

क्रिप्टोकॉइन्स बाजार में एक बार फिर निराशा का माहौल है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप करीब 1.30 फीसदी गिरकर लगभग 2.52 ट्रिलियन डॉलर पर आ गया, जिससे बिटकॉइन और इथेरियम सहित अधिकांश प्रमुख डिजिटल संपत्तियों में गिरावट दर्ज की गई। इस मंदी के दौर में भी एक अज्ञात क्रिप्टोकॉइन्स जीनियस टर्मिनल ने पिछले सात दिनों में निवेशकों को 227 फीसदी से अधिक का शानदार रिटर्न देकर सबको चौंका दिया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वैश्विक क्रिप्टो बाजार पूंजीकरण में लगभग 1.30

फीसदी की कमी आई है, जिससे यह 2.52 ट्रिलियन डॉलर पर स्थिर हो गया है। बाजार में कमजोरी के बावजूद सोमवार सुबह फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में 1 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 51 पर पहुंच गया, जो निवेशकों के बीच एक न्यूट्रल भावना को दर्शाता है। हालांकि, यह आंकड़ा पिछले सप्ताह के मुकाबले लगभग स्थिर बना हुआ है। इस गिरावट का सबसे बड़ा असर प्रमुख क्रिप्टोकॉइन्स पर देखने को मिला। बाजार की सबसे बड़ी क्रिप्टोकॉइन्स बिटकॉइन करीब 1.5 फीसदी टूटकर 74,595 डॉलर पर आ गई, जबकि एथेरियम में लगभग 2.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई और इसकी कीमत



2,283 डॉलर हो गई। अन्य प्रमुख डिजिटल संपत्तियों जैसे एक्सआरपी, सोलोना और हाइपर लिक्विड में भी 1.5 से लेकर 5 फीसदी तक की गिरावट देखी गई। ऐसे गिरते बाजार में जहां अधिकांश निवेशक नुकसान झेल रहे थे, वहीं जीनियस टर्मिनल नामक क्रिप्टोकॉइन्स ने असाधारण प्रदर्शन किया। पिछले 7 दिनों में इस कॉइन् ने निवेशकों को 227 फीसदी से अधिक का चौंका देने

वाला रिटर्न दिया, जिसका मतलब है कि यदि किसी ने इसमें एक लाख रुपये का निवेश किया होता तो वह बढ़कर तीन लाख रुपये से अधिक हो सकता था। हालांकि, पिछले 24 घंटों में इसमें 6 फीसदी से अधिक की गिरावट आई और इसकी कीमत चटकर लगभग 0.6271 डॉलर पर आ गई। बाजार की इस मंदी के बावजूद, कुछ अन्य क्रिप्टोकॉइन्स ने भी सकारात्मक प्रदर्शन किया।

## अनलिस्टेड शेयर में 9 प्रतिशत गिरावट



मुंबई ।

एनएसई के संभावित आईपीओ को लेकर बनी उत्सुकता के बीच अनलिस्टेड मार्केट में इसके शेयरों में करीब 9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी में 2,075 रुपये पर कारोबार करने वाला शेयर अब लगभग 1,885 रुपये तक आ गया है। गिरावट की मुख्य वजह सख्त नियम और निवेशकों की सतर्कता मानी जा रही है। करीब 20,000 करोड़ रुपये के इस ऑफर फंड सेल में कैवल पुराने निवेशकों को ही हिस्सेदारी बेचने की अनुमति होगी, जिससे नए निवेशक इस दौड़ से बाहर हो गए हैं।

## डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म रेजरपे आईपीओ की जल्द करेगा घोषणा

- कंपनी की इस इश्यू के जरिए 600-700 मिलियन डॉलर जुटाने की योजना



मुंबई ।

डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म रेजरपे जल्द ही अपना प्रारंभिक सार्वजनिक निगम (आईपीओ) लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी इस इश्यू के जरिए 600-700 मिलियन डॉलर जुटाने की योजना बना रही है। इसकी संभावित वैल्यूएशन 5-6 बिलियन डॉलर आंकी गई है, जो इसके पूर्व के पीक से काफी कम है और बाजार में स्टार्टअप के प्रति बढ़ती सतर्कता का संकेत है। रेजरपे कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग रूट का इस्तेमाल करेगी, जिसके तहत कंपनियां अपने वित्तीय विवरणों को तुरंत सार्वजनिक किए बिना सेबी के पास आईपीओ दस्तावेज जमा कर सकती हैं। यह रणनीति हाल के समय में स्विंग, ग्रे और मोशो जैसी कंपनियों द्वारा भी अपनाई गई है, जो उन्हें बाजार की स्थिति को देखते हुए लचीलापन देती है। हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि

रेजरपे की संभावित वैल्यूएशन 5-6 बिलियन डॉलर है, जो 2022 में इसके 7.5 बिलियन डॉलर के पीक से काफी कम है। यह गिरावट बढ़ती प्रतिस्पर्धा, थीमी पेमेंट ग्रोथ और कंपनी के लगातार घाटे के बीच आई है। सार्वजनिक बाजार के निवेशक अब पहले की तुलना में अधिक चयनात्मक हो गए हैं और वे उन कंपनियों को प्राथमिकता दे रहे हैं जिनके पास स्पष्ट मुनाफे का रोजमैप या मजबूत ग्रोथ नंबर हों। हाल ही में फोनपे ने भी कम वैल्यूएशन ऑफर होने के कारण अपने आईपीओ की योजना को फिलहाल टाल दिया था। ऐसे में रेजरपे को निवेशकों को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और भविष्य की ग्रोथ को लेकर आश्वासन देना होगा। यह आईपीओ भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण टेस्ट साबित होगा कि बाजार अब हाई वैल्यूएशन के बजाय यथार्थवादी मूल्यांकन पर कितना जोर देता है।

## अमेरिका में अवैध आयात शुल्कों का रिफंड शुरू, अरबों डॉलर वापसी का मार्ग प्रशस्त

60 से 90 दिन में मिलेगी राशि; उपभोक्ताओं को भी अप्रत्यक्ष लाभ की उम्मीद



वॉशिंगटन ।

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए विवादास्पद आयात शुल्कों की वापसी का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय द्वारा इन शुल्कों को अस्वैधानिक करार दिए जाने के बाद संबंधित कंपनियों के लिए रिफंड का दावा दाखिल करने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। यह उन हजारों आयातकों के लिए राहत लेकर आया है जिन्होंने अरबों डॉलर का भुगतान किया था। अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (सीबीपी) के अनुसार, आयातक और उनके एजेंट सोमवार सुबह आठ बजे से एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रिफंड का दावा कर सकते हैं। सीबीपी ने बताया कि स्वीकृत दावों पर

रिफंड जारी होने में 60 से 90 दिन का समय लग सकता है। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी, जिसमें पहले हाल ही में किए गए भुगतान शामिल होंगे। न्यायालय ने माना था कि ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया था, जिससे अमेरिकी संसद के कर निर्धारण अधिकार का उल्लंघन हुआ। सीबीपी के आंकड़ों के मुताबिक, लगभग 3,30,000 आयातकों ने करीब 166 अरब डॉलर के शुल्क का भुगतान किया था। हालांकि, फिलहाल रिफंड प्रक्रिया के पहले चरण में कुछ ही मामलों को शामिल किया गया है। इस निर्णय से कुछ मामलों में उपभोक्ताओं को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की संभावना है, हालांकि यह प्रक्रिया धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी।

# नारी सम्मान की पुकार में विपक्ष की पराजय और संघर्ष में भी विजय का विश्वास



कातिलाल मांडोट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस पीड़ा और प्रतिबद्धता के साथ देश को संबोधित किया वह केवल एक नेता का वक्तव्य नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नेतृत्व का संकेत था। उन्होंने यह स्वीकार किया कि महिला आरक्षण जैसे संवैधानिक विषय पर विपक्ष और अधिक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेगा यह दृष्टिकोण जनता के भीतर विश्वास पैदा करता है कि प्रयास सच्चे हैं और दिशा स्पष्ट है।

देश की राजनीति के वर्तमान दौर में महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि जनभावनाओं और राजनीतिक दृष्टिकोण का आईना बनकर सामने आया है इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कौन वास्तव में नारी सशक्तिकरण के साथ खड़ा है और कौन इस विषय को केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। संसद में जो कुछ हुआ और उसके बाद जिस प्रकार से बयानबाजी और रणनीतियां सामने आईं उसने लोकतंत्र की परिपक्वता और दलों की मंशा दोनों को उजागर कर दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस पीड़ा और प्रतिबद्धता के साथ देश को संबोधित किया वह केवल एक नेता का वक्तव्य नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नेतृत्व का संकेत था। उन्होंने यह स्वीकार किया कि महिला आरक्षण विधेयक पारित न हो पाने का उन्हें दुःख है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह संघर्ष यहीं समाप्त नहीं होगा बल्कि और अधिक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेगा यह दृष्टिकोण जनता के भीतर विश्वास पैदा करता है कि प्रयास सच्चे हैं और दिशा स्पष्ट है।

विपक्षी खेमे में राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे जैसे नेताओं की बैठकों और प्रेस वाताओं ने यह दर्शाया कि वे इस मुद्दे को जनहित की बजाय राजनीतिक अवसर के रूप में अधिक देख रहे हैं। महिला आरक्षण जैसे संवैधानिक विषय पर स्पष्ट और ठोस समर्थन देने के बजाय उन्होंने शर्तों और संशोधनों की बात कर अपने रुख को कमजोर किया है। यह जनता के सामने उनकी प्राथमिकताओं को उजागर करता है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि विपक्ष अब यह कह रहा है कि पुराने विधेयक को वर्तमान सीटों पर लागू किया जाए लेकिन जब अवसर था तब उन्होंने उसी विधेयक को समर्थन क्यों नहीं दिया। यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। जनता इस विरोधाभास को भलीभांति समझ रही है और यह स्थिति विपक्ष की विश्वसनीयता को कमजोर करती है। परिसीमन के मुद्दे पर भी जिस प्रकार से भ्रम फैलाने की कोशिश की गई वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ न्याय नहीं



है यह एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य प्रतिनिधित्व को संतुलित करना है। लेकिन इसे क्षेत्रीय असंतुलन और राजनीतिक नुकसान के रूप में प्रस्तुत करना केवल जनता को भ्रमित करने का प्रयास प्रतीत होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य में इस भ्रम को दूर करने का प्रयास किया और यह स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया सभी राज्यों के लिए समान रूप से लागू होती है। इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा और एनडीए की रणनीति अधिक स्पष्ट और संगठित दिखाई देती है जहां एक ओर वे संसद में अपने प्रयासों के माध्यम से विधेयक को पारित कराने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर अब वे जनता के बीच जाकर इस विषय को समझाने का संकल्प ले रहे हैं। यह सक्रियता और आत्मविश्वास यह दर्शाता है कि वे इस मुद्दे को केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखते हैं।

विपक्ष द्वारा देशभर में अभियान चलाने और सरकार के खिलाफ वातावरण बनाने की बात यह दर्शाती है कि वे संसद में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने में असफल रहे अब वे सड़कों पर संघर्ष के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज की जागरूक जनता केवल नारों और आरोपों से प्रभावित नहीं होती वह कार्य और नीयत दोनों को परखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जिस प्रकार से परिवारवाद और स्वार्थी राजनीति का उल्लेख किया वह भारतीय राजनीति की एक पुरानी समस्या की ओर संकेत करता है। जब निर्णय समाज के व्यापक हित की बजाय कुछ परिवारों के हित में लिए जाते हैं, तब विकास और समान अवसर बाधित होते हैं। महिला आरक्षण जैसे विषय ऐसे ढांचे के लिए चुनौती बनते हैं क्योंकि यह नई नेतृत्व क्षमता को जन्म देता है और सत्ता के केन्द्रिकरण को तोड़ता है।

इस पूरे प्रकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि आज की नारी केवल दर्शक नहीं है वह सक्रिय रूप से राजनीति और समाज को समझ रही है। वह यह देख रही है कि कौन उसके अधिकारों के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहा है और कौन केवल दिखावे की राजनीति कर रहा है। यह जागरूकता भविष्य के राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करेगी।

कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के लिए यह स्थिति एक बड़ी राजनीतिक चुनौती के रूप में सामने आई है। इनकी रणनीति में स्पष्टता की कमी और उनके बयानों में विरोधाभास ने उन्हें कमजोर स्थिति में ला खड़ा किया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस मुद्दे पर उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है यह हार केवल संसद में नहीं बल्कि जनमानस में भी दिखाई दे रही है।

दूसरी ओर एनडीए के लिए यह एक अलग प्रकार की स्थिति है, जहां विधेयक पारित न हो पाने के बावजूद उन्होंने नैतिक और वैचारिक स्तर पर एक मजबूत स्थान प्राप्त किया है। यह स्थिति है जहां संघर्ष में भी जीत का अनुभव होता है। क्योंकि उद्देश्य स्पष्ट और प्रयास निरंतर हैं जनता इस अंतर को समझती है और यही समझ भविष्य में उनके समर्थन का आधार बन सकती है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि महिला आरक्षण और परिसीमन का यह पूरा घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया है। इसमें जहां एक ओर विपक्ष की कमजोरियां उजागर हुईं हैं वहीं दूसरी ओर एनडीए की दृढ़ता और संकल्प सामने आया है। यह संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वे यह बताते हैं कि जनता अब अधिक सजग है और वह सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए तैयार है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी है।

## संपादकीय

### मानव हित सर्वोपरि

हमारे समाज के बुद्धिजीवी, अध्यात्मिक व सामाजिक चिंतक गाहे-बगाहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मानवीय मूल्यों के क्षरण पर लगातार चिंता जताते रहे हैं। अब इस चिंता पर पोप लियो 14 की स्वीकारिता ने मोहर लगायी है। उन्होंने आशंका जतायी है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से वैश्विक ध्वनीकरण, संघर्ष, भय और हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है। उनके इस बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ऐसे वक्त में जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सुविधा, गति व नवाचार के लिये सराहा जा रहा है, पोप ने चेतावनी है कि नैतिकता के बिना प्रौद्योगिकी घातक साबित हो सकती है। इसमें दो राय नहीं कि मूल रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता बुरी नहीं है, लेकिन यह तटस्थ भी नहीं है। निस्संदेह, इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता कि संस्थान व सरकारें इसे कैसे डिजाइन करती हैं और कैसे इसका उपयोग करती हैं। हाल की कुछ घटनाओं ने इन चिंताओं की पुष्टि भी की है। विभिन्न देशों के लोकतांत्रिक चुनाव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निर्मित डीपफेक और क्लोन की गई आवाजों का प्रयोग झूठे विमर्शों को फैलाने, मतदाताओं को भ्रमित करने में किया गया। जिससे दुनिया में लोकतांत्रिक संस्थानों के प्रति जनता का भरोसा टूटा है। यह खतरनाक है कि साइबर ठगों ने क्लोनिंग उपकरणों के जरिये आवाज का उपयोग परिवार के सदस्यों व अधिकारियों के रूप में किया है। इसके जरिये साइबर अपराधियों ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को जीवन भर की पूंजी तक लुटा है।

विडंबना है कि जिस कार्य को अब तक तकनीकी-कौशल व संसाधनों के जरिये किया जाता था, वह तकनीक से अब आसानी व बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग भ्रामक सूचनाओं के लिये ही नहीं किया जा रहा है। आशंका है कि उन्नत एआई के जरिये वित्तीय प्रणालियों और साइबर सुरक्षा को खतरा पैदा किया जा सकता है। चिंता है कि शक्तिशाली एआई तकनीक से वित्तीय व्यवस्था की कमजोर कड़ियों को निशाना बनाया जा सकता है। जिसे पकड़ना नियामक संस्थाओं के लिये मुश्किल होगा। ये स्वचालित हमले बैंकिंग नेटवर्क में धोखाधड़ी करने में सक्षम हो सकते हैं। जो हमारी डिजिटल दुनिया से भी आगे घातक प्रभाव डाल सकते हैं। जिससे देशों में वित्तीय संकट पैदा हो सकते हैं। भ्रुणदान व्यवस्था में व्यवधान व विश्वास से छल तथा राजनीतिक दुरुपचार से समाज में अस्थिरता पैदा हो सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पर्यावरणीय घातक प्रभाव भी कम नहीं हैं। एआई के विस्तार के लिये विशाल डेटा केंद्रों, कोबाल्ट व लिथियम जैसे खनिजों की खुदाई की जरूरत होती है। जिसके लिये भारी पर्यावरणीय व मानवीय लागत की जरूरत होती है। निस्संदेह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में न तो इसे नकारा ही जा सकता है और न ही ये बुद्धिमत्ता का फैसला होगा, लेकिन इसका जिम्मेदारी से प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चिकित्सा, शिक्षा, आपदा प्रबंधन व उत्पादकता में यह रामबाण सिद्ध हो सकती है, लेकिन यह मजबूत कानून, कंपनियों के सिस्टम की पारदर्शिता व सुरक्षा से ही निरापद हो सकती है। नागरिकों की डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना होगा।

### चिंतन-मनन

## सबसे अच्छा सखा है ज्ञान

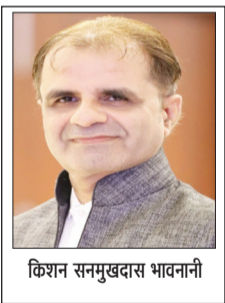
आत्मा ही आनन्द का स्वरूप है। किसी भी सुखद अनुभूति में तुम आंखे मूंद लेते हो। जैसे जब किसी फूल को सूंघते हो, कोई स्वादिष्ट खाना चखते हो या किसी वस्तु को स्पर्श करते हो। दुःख का केवल यही अर्थ है कि तुम अपरिवर्तनीय आत्मा पर केन्द्रित होने के बदले विषयवस्तु में फंसे हो, जो परिवर्तनीय है। सभी इन्द्रियां केवल डार्विंग बोर्ड की भांति हैं जो तुम्हें वापस आत्मा तक पहुंचाती हैं। स-खा का अर्थ है वह ही इन्द्रिय है। सखा वह है जो तुम्हारी इन्द्रिय बन गया है, जो तुम्हारी इन्द्रिय ही है। यदि तुम मेरी इन्द्रिय हो, इसका मतलब तुम्हारे द्वारा मुझे ज्ञान मिलता है, तुम मेरी छठी इन्द्रिय है। जैसे मैं अपने मन पर विश्वास करता हूँ, वैसे ही मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। एक मित्र केवल इन्द्रिय-विषय हो सकता है, परन्तु सखा स्वयं इन्द्रिय बन जाता है।

सखा वह साथ है जो सुख और दुःख, दोनों अनुभवों में साथ रहता है। सखा वह है जो तुम्हें आत्म स्थिर करता है, यदि तुम किसी विषय वस्तु में फंसे हो। जो ज्ञान तुम्हें वापस आत्मा की ओर लाता है, वही सखा है। ज्ञान तुम्हारा साथी है और गुरु केवल ज्ञान के प्रतिरूप हैं। सखा का अर्थ है, वह मेरी इन्द्रियां हैं। मैं संसार को उसी ज्ञान के द्वारा, उनके माध्यम से देखता हूँ। यदि तुम्हारी सोच देवी है, तो तुम समस्त संसार को दिव्य दृष्टि से देखोगे। कुछ वर्षों में तुम्हारा मस्तक मिट्टी में होगा, जीते जी तो अपना सर कीचड़ से मत भरो। मेरा पीछा न करो। वास्तव में तुम मेरा पीछा कर भी नहीं सकते, क्योंकि मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ, तुमको आगे उलटने के लिए। तुम्हें सब-कुछ पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ना है। सब कुछ तुम्हारे सभी अनुभव, तुम्हारे नाते-रिश्ते-भूत काल के हिस्से हैं। सब-कुछ छोड़ दो। अपनी स्थितियों के सम्पूर्ण संसार को पीछे छोड़ दो। मुझको भी आगे बढ़ो और मुक्त हो जाओ। कुछ और खोजना बन्द करो- तब तुम मुक्त होगे और तुममें अनुकम्पा उभरेगी।



संजय गोस्वामी

शनिवार 18 अप्रैल 26 को भारत सरकार के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, ईरानी आईआरजीसी ने नौसेना की गनबोटों ने भारतीय ध्वज वाले टैंकरों के पास चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं। भारतिय दो टैंकर पर आई आर जी सी ने गोली चला दी भारत ने होर्मुज स्ट्रेट पर दो भारतीय जहाजों पर हुई गोलीबारी की घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए देश में ईरान के राजदूत को तलब किया। हालांकि, विदेश मंत्रालय के बयान में समन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन यह संकेत दिया गया कि ईरानी राजदूत फाथली को शनिवार शाम जवाहरलाल नेहरू भवन में विदेश सचिव से मिलने के लिए कहा गया था। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने शनिवार (18 अप्रैल) शाम को भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथली को तलब किया और होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरानी युद्धपोतों द्वारा दो भारतीय जहाजों पर की गई गोलीबारी पर हर्षगंभीर चिंता जताई है।



किशन सन्मुखदास भानवानी

वैश्विक स्तर पर शेर बाजार को अक्सर केवल आर्थिक आंकड़ों, कॉर्पोरेट प्रदर्शन और वैश्विक संकेतकों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। बाजार का एक महत्वपूर्ण आधार विश्वास (कॉन्फिडेंस) होता है, और यह विश्वास सीधे तौर पर राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता और शासन की विश्वसनीयता से जुड़ा होता है। 16-17 अप्रैल 2026 के संसदीय घटनाक्रम ने इसी विश्वास को झकझोरने का काम किया। एक तरफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम को आधी रात में लागू किया गया, वहीं दूसरी ओर संवैधानिक संशोधन विधेयक का गिर जाना बाजार के लिए एक जटिल संकेत बनकर उभरा। मैं एडवोकेट किशन सन्मुखदास भानवानी गौदिया महाराष्ट्र यह मानता हूँ कि यह घटनाक्रम केवल राजनीतिक नहीं था इसने निवेशकों के मनोविज्ञान, विदेशी पूंजी प्रवाह, और भारतीय शेर बाजार की दिशा को प्रभावित करने की क्षमता दिखाई। लोकसभा में 528 संसदों द्वारा मतदान, जिसमें 298 समर्थन और 230 विरोध में वोट पड़े, लेकिन दो-तिहाई बहुमत की कमी के कारण विधेयक का गिर जाना यह एक सामान्य संसदीय घटना नहीं थी शेर बाजार के दृष्टिकोण से यह पॉलिटी फेलियर सिग्नल (नीतिगत विफलता का संकेत) है। जब कोई सरकार बड़ा संवैधानिक संशोधन पास नहीं कर पाती, तो निवेशकों को यह संकेत मिलता है कि भविष्य में भी बड़े आर्थिक सुधारों को लागू करना कठिन हो सकता है। यहाँ से बाजार में अनिश्चितता का प्रवेश होता है और अनिश्चितता ही शेर बाजार की सबसे बड़ी और सटीक दुश्मन होती है।

साथियों बात अगर हम इस पूरे प्रकरण को भारत की आर्थिक प्रतिष्ठ और दृष्टिकोण से वैश्विक निवेशकों की दृष्टि: नीतिगत निरंतरता का संकेत के रूप में समझने की

करें तो अंतरराष्ट्रीय निवेशक और संस्थागत निवेशक किसी भी देश में निवेश करते समय केवल आर्थिक आंकड़ों को नहीं देखते, बल्कि वे राजनीतिक स्थिरता और नीतिगत निरंतरता को भी समान महत्व देते हैं। जब संसद में कोई प्रमुख संवैधानिक संशोधन विधेयक विफल होता है, तो यह संकेत देता है कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल या राजनीतिक सहमति नहीं है। इस संदर्भ में इंटरनेशनल मोनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान भी ऐसे घटनाक्रमों को गंभीरता से देखते हैं। इससे देश की जोखिम प्रोफाइल (रिस्क परसेप्शन) प्रभावित होती है, जो विदेशी पूंजी प्रवाह (कैपिटल इन्फ्लो) पर तत्काल प्रभाव डाल सकती है। शेर बाजार की मनोविज्ञान: अनिश्चितता का तात्कालिक प्रभाव पर आधारित होता है, शेर बाजार मूलतः अपेक्षाओं और विश्वास पर आधारित होता है। जब सरकार के बड़े विधेयक विफल होते हैं, तो निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ जाती है। इसका परिणाम अल्पकालिक गिरावट या अस्थिरता के रूप में सामने आ सकता है। विश्व रूप से जब बाजार पहले से गिरावट के दौर में हो, तब इस प्रकार की राजनीतिक घटनाएँ निवेशकों की चिंता को और बढ़ा देती हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक अक्सर ऐसी स्थितियों में अपने निवेश को अस्थायी रूप से कम कर देते हैं, जिससे बाजार में गिरावट बहुत ही तेज हो सकती है। साथियों बात अगर हम रूल् 66 और बाजार की प्रतिक्रिया: प्रक्रिया बनाम परिणाम को समझने की करें तो, संसद में रूल 66 को निलंबित करना और तीन विधेयकों को एक साथ जोड़ना केवल राजनीतिक रणनीति नहीं थी, बल्कि यह बाजार के लिए एक ह्यूमोरोस जलडमरूमध्य (प्रक्रियागत जोखिम) का संकेत था। निवेशक केवल यह तत्काल प्रतिक्रिया: गिरावट, अस्थिरता और एफआईआई की रणनीति। ऐसे घटनाक्रमों के बाद आमतौर पर तीन प्रकार की प्रतिक्रियाएँ देखने को मिलती हैं: शॉर्ट-टर्म गिरावट (शार्ट - टर्म-करेक्शन) : निवेशक घबराहट में बिकवाली शुरू करते हैं, जिससे बाजार में गिरावट आती है। लॉन्ग-टर्म (वोलैटिलिटी) : वोलैटिलिटी (वोलैटिलिटी) में वृद्धि: बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ जाता है, क्योंकि निवेशक स्पष्ट दिशा नहीं समझ पाते।

साथियों बात अगर हम फरिन इस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स का सतर्क रवैया: इसको समझने की करें तो विदेशी निवेशक अस्थायी रूप से निवेश घटा सकते हैं या 'वेट एंड वाच' रणनीति अपनाते हैं। यह वही स्थिति है जो 16-17 अप्रैल के बाद देखने को मिल सकती है विशेषकर तब, जब बाजार पहले से गिरावट के दबाव में हो। वैश्विक निवेशक जैसे इंटरनेशनल मोनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से जुड़े निवेशक किसी भी देश की निवेश क्षमता को तीन प्रमुख आधारां पर आंकते हैं: (1) राजनीतिक स्थिरता (2) नीतिगत निरंतरता (3) संस्थागत पारदर्शिता जब संसद में बड़ा विधेयक गिरता है, तो यह संकेत जाता है कि सरकार को व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। इससे पोलिटिकल रिस्क इंडेक्स बढ़ता है, जो सीधे तौर पर निवेश निर्णयों को प्रभावित करता है। साथियों बात अगर हम रुफया, बॉन्ड मार्केट और इक्विटी मार्केट पर संयुक्त प्रभाव इसको समझने की करें तो इस प्रकार की राजनीतिक अनिश्चितता का असर केवल शेर बाजार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह तीन स्तरों पर प्रभाव डालता है: (1) रुफया (करेंसी) : विदेशी निवेशक यदि पैसा निकालते हैं, तो रुफये पर दबाव बढ़ता है और वह डॉलर के मुकाबले कमजोर हो सकता है। (2) बॉन्ड मार्केट: सरकारी नीतियों पर भरोसा कम होने से बॉन्ड यील्ड बढ़ सकती है, जिससे उधारी महंगी हो जाती है। (3) इक्विटी मार्केट: कंपनियों के भविष्य के मुनाफे पर अनिश्चितता बढ़ने से शेयरों की कीमतों में गिरावट आ सकती है। महिला सशक्तिकरण और बाजार का दीर्घकालिक दृष्टिकोण। हालांकि अल्पकालिक प्रभाव नकारात्मक हो सकता है, लेकिन महिला सशक्तिकरण जैसे सुधार दीर्घकाल में बाजार के लिए अत्यंत सकारात्मक होते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार यदि महिला श्रम भागीदारी में वृद्धि होती है, तो जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। इसका सीधा प्रभाव शेर बाजार पर पड़ता है, क्योंकि: (1) उपभोक्ता मांग बढ़ती है। (2) कंपनियों की बिक्री और मुनाफा बढ़ता है। (3) आर्थिक गतिविधि तेज होती है। अर्थात्, महिला आरक्षण जैसे कदम बाजार के लिए 'लॉन्ग - टर्म बुलिश ट्रिगर' बन सकते हैं। भले ही अल्पकाल में अनिश्चितता हो।

साथियों बात अगर हम स्टॉटअप इकोसिस्टम और निवेशकों में विश्वास को समझने की करें तो: बाजार के लिए नया जोखिम- भारत का शेर बाजार इस समय एक और चुनौती का सामना कर रहा है स्टॉटअप बनाम पारंपरिक अर्थव्यवस्था का संघर्ष। जीटी, ब्लॉकिट और स्टिग्मी



सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है इसलिए भारत को इसका कड़ा जबाब देना चाहिए नहीं तो पाकिस्तान और ईरान दोनों की सीमा सटती है वहाँ से तो आतंकवाद होता रहता है अब यदि धर्म के नाम पर ईरान भी इसी रास्ते चला तो आने वाले समय में आतंकवादी घटना बढ़ेगी लेकिन यहाँ तो एक नारी शक्ति बिल पर राजनीति हो रही जो संसद में पास नहीं हुआ। लोकतंत्र है ऐसा होता है इसका सम्मान करना चाहिए हालांकि मुझे भी दुःख है लेकिन अदालत तो संसद के निर्णय को ही सही मानेगी अगर गलत है तो अगले चुनाव में पूर्ण बहुमत दे देना लेकिन राष्ट्र हित में जो निर्णय लिए जाएं वो सही हो इसलिए इस मुद्दे पर कार्यवाही करना चाहिए।

## राजनीति और शेर बाजार-एक अदृश्य लेकिन गहरा संबंध- विदेशी निवेशकों की मानसिकता: स्थिरता ही सर्वोच्च प्राथमिकता

इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म ने तेजी से विस्तार किया है। वहीं आल इंडिया कंस्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने इनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। जैसे प्रेडेटरी प्रैक्टिस और पारंपरिक रिटेल को नुकसान। आईपीओ बाजार पर संभावित असर: वैल्यूएशन बनाम वास्तविकता, यदि घाटे में चल रही कंपनियाँ उच्च वैल्यूएशन पर आईपीओ लाती हैं, तो यह बाजार में बल पाठमंशण का संकेत हो सकता है। (1) निवेशकों के लिए जोखिम : (2) ओवरवैल्यूएशन पर निवेश (3) लिस्टिंग के बाद गिरावट (4) बाजार में भरोसे की कमी, यदि ऐसे आईपीओ असफल होते हैं, तो यह पूरे टेक सेक्टर और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकता है।

साथियों बात अगर हम निवेशक साख और बाजार की विश्वसनीयता इसको समझने की करें तो, नियामक संस्थाओं की भूमिका इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि वे निवेशकों के हितों की रक्षा नहीं कर पाते, तो बाजार की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ सकता है। यह स्थिति विदेशी निवेशकों के लिए एक 'रेड फ्लैग' बन सकती है, जिससे वे अन्य देशों की ओर रुख कर सकते हैं। साथियों बात अगर हम राजनीतिक घटनाक्रम और बाजार के बीच संबंध को सार इसको समझने की करें तो 16-17 अप्रैल 2026 की घटनाएँ यह स्पष्ट करती हैं कि राजनीति और बाजार अलग-अलग नहीं हैं, नीतिगत अनिश्चितता बाजार को तुरंत प्रभावित करती है, निवेशकों का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण कारक है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि क्या यह गिरावट अवसर है या चेतावनी? शेर बाजार में हर गिरावट केवल जोखिम नहीं होती कई बार यह अवसर भी होती है। यदि सरकार आने वाले समय में नीतिगत स्पष्टता बढ़ाती है, आर्थिक सुधारों को जारी रखती है, निवेशकों का विश्वास बहाल करती है, तो यह गिरावट एक 'बाइंग अपोर्चिनिटी' बन सकती है। लेकिन यदि अनिश्चितता बनी रहती है, तो यह बाजार के लिए एक दीर्घकालिक चुनौती बन सकती है। इसलिए, भारतीय शेर बाजार का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि देशराजनीतिक स्थिरता और आर्थिक सुधारों के बीच संतुलन कैसे स्थापित करता है क्योंकि आज का निवेशक केवल आंकड़ों से नहीं, बल्कि विश्वास से निवेश करता है। (यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं। इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।)

## संक्षिप्त समाचार

ट्रंप ने विवादित विधेयक पर हस्ताक्षर किए, निगरानी कार्यक्रम का 30 अप्रैल तक विस्तार; अब संसद में होगी बहस

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद एक विवादित निगरानी कार्यक्रम को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। यह कम अवधि का विस्तार है। इसके बाद अब इस मुद्दे पर कांग्रेस (संसद) में बहस होने की संभावना है। यह विधेयक शुक्रवार को सीनेट में अंतिम क्षण में पारित किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निगरानी का अधिकार कुछ ही दिनों में समाप्त न हो जाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताया और इसके नवीनीकरण का समर्थन किया। हालांकि, आलोचक इसे नागरिकों की आजादी के लिए खतरा मान रहे हैं। इस विवाद के केंद्र में 'धारा 702' है। यह विदेशी खुफिया निगरानी कानून का हिस्सा है। यह धारा केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी (सीआईए), राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनएसए), सशरीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) और अन्य एजेंसियों को बिना वारंट के विदेशी संचार को बड़ी मात्रा में एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने की अनुमति देती है। इस प्रक्रिया में कभी-कभी अमेरिकी नागरिकों के संदेश भी शामिल हो जाते हैं, अगर वे विदेशी लक्ष्यों से संपर्क में हों।

'ट्रंप प्रशासन के लिए खतरा है मुनीर, ईरान से करीबी संबंध', अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का बड़ा दावा

वाशिंगटन, एजेंसी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए एक संभावित 'रेड फ्लैग' यानी जोखिम साबित हो सकते हैं। इसकी वजह उनके ईरान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व से लंबे समय से संबंध बनाए जा रहे हैं। फॉक्स न्यूज की हालिया रिपोर्ट और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की आकलन रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में ईरानी नेतृत्व से गहरे और लंबे समय से संबंधों के कारण मुनीर को उनके ट्रंप प्रशासन के लिए एक संभावित जोखिम बताया गया है। पाकिस्तान के सेनापति जनरल ने फॉक्स न्यूज डिजिटल को बताया कि मुनीर के ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, जिनमें कुदस फोर्स के मारे गए कमांडर कासिम सुलेमानी और आईआरजीसी कमांडर होसेन सलामी शामिल हैं। ये संबंध ऐसे समय में चर्चा में हैं, जब मुनीर अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच पीछे वाले दरवाजे से संघर्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इस भूमिका के तहत वह दोनों देशों के बीच गोपनीय स्तर पर संचालित बनाए रखने और बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से मुनीर की प्रशंसा करते हुए उन्हें अपना 'पसंदीदा फील्ड मार्शल' बताया है। लेकिन, खुफिया अधिकारियों का कहना है कि उनकी दोहरी भूमिका अमेरिकी हितों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। फोक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के इतिहास को देखते हुए, खासकर अफगानिस्तान में उसकी भूमिका को लेकर उसे एक 'भरोसेमंद सहयोगी नहीं' माना जा सकता है। इसलिए, उनके ईरान के साथ नजदीकी संबंध को सुरक्षा के लिए जोखिम के रूप में देखा जा रहा है।

ट्रंप से बहस करना बिल्कुल भी मेरे हित में नहीं, पोप लियो बोले- मेरा काम दुनिया में शांति को बढ़ावा देना है

कैम्ब्रिज, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई तीखी आलोचनाओं पर विराम लगाते हुए पोप ने बड़े ही सौम्य लेकिन दृढ़ शब्दों में कहा कि ईरान युद्ध को लेकर 'राष्ट्रपति के साथ बहस करना बिल्कुल भी मेरे हित में नहीं है'। कैम्ब्रिज से अंगोला की उड़ान के दौरान पोप लियो चौदहवें ने एक बार फिर दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि उनका मिशन राजनीति नहीं, बल्कि शांति है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई तीखी आलोचनाओं पर विराम लगाते हुए पोप ने बड़े ही सौम्य लेकिन दृढ़ शब्दों में कहा कि ईरान युद्ध को लेकर 'राष्ट्रपति के साथ बहस करना बिल्कुल भी मेरे हित में नहीं है'। पिछले कुछ दिनों से ट्रंप और वेटिकन के बीच वाक्युद्ध का जो दौर चल रहा था, उस पर पोप ने स्पष्ट किया कि शांति का उनका प्रचार किसी व्यक्ति विशेष (ट्रंप) के लिए नहीं, बल्कि ईसा मसीह के उपदेशों पर आधारित है। ट्रंप ने उन पर अपराधों को लेकर 'नरम' होने और वामपंथियों का करीबी होने का आरोप लगाया था, यहां तक कि उनके चयन का श्रेय भी खुद को दिया था। इसके जवाब में पोप ने कहा कि मेरे बयानों का उद्देश्य किसी राजनीतिक विवाद को जन्म देना नहीं था। उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध और अफ्रीका के आंतरिक संघर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर युद्ध का औचित्य साबित करना गलत है। 'मैं मुख्य रूप से एक पादरी के रूप में, कैथोलिक चर्च के प्रमुख के रूप में अफ्रीका आया हूँ। मेरा काम दुनिया में न्याय, भाईचारा और शांति को बढ़ावा देना है।

## अमेरिकी प्रतिबंध के बाद क्यूबा में ईंधन संकट गहराया, स्पेन समेत कई देशों ने जताई चिंता

मैड्रिड, मैड्रिड, एजेंसी। जनवरी के आखिर में वाशिंगटन द्वारा तेल की सप्लाई रोकने के बाद क्यूबा की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं मिल रहा है। ईंधन के अभाव में इन तीन महीनों में वहां मानवीय स्थिति एक गंभीर मोड़ पर पहुंच गई है। इस बीच ब्राजील, मैक्सिको और स्पेन की सरकारों ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है और स्थिति को आसान बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। स्पेन के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित एक संयुक्त बयान में यह जानकारी दी गई है। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को तीनों सरकारों ने संबंधित पक्षों से यह भी अपील की कि वे ऐसे लक्ष्यों की कदम से बचें, जिससे लोगों के जीवन की स्थितियां और खराब हों या जिससे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो। इसके साथ ही उन्होंने क्यूबा के लोगों की तकलीफों को कम करने के

लिए एक समन्वित तरीके से अपनी मानवीय सहायता को बढ़ाने का भी संकल्प लिया। अपने बयान में ब्राजील, स्पेन और मैक्सिको ने हर समय अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की आवश्यकता को भी दोहराया। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में निहित क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभु समानता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों का पालन करने पर भी जोर दिया। उन्होंने मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों और बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातचीत का मकसद मौजूदा हालात का कोई पक्का हल निकालना होना चाहिए और यह पक्का करना ऊर्जा संकट का अंतर और भी ज्यादा बिगड़ने का समाधान नहीं है। देश में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने कहा, 'सौमित मानवों को सप्लाई पहुंचाने की खबरों के बावजूद रूस से भेजी गई तेल की एक



हालिया खेप को पिछले हफ्ते अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद बंदरगाह पर उतरने की इजाजत दी गई थी। देश में मानवीय जरूरतें अभी लगातार बनी हुई हैं। मार्च के आखिर से ऊर्जा संकट का अंतर और भी ज्यादा बिगड़ गया है। 'बता दें कि क्यूबा की ऊर्जा जरूरतें जनवरी में अमेरिका द्वारा राष्ट्रपति निकोलस माद्रुरो को सौंपे जाने तक बड़े पैमाने पर वेनेजुएला द्वारा पूरी की जाती थीं।

ब्राजील-स्पेन और मैक्सिको ने क्या कहा: अपने बयान में ब्राजील, स्पेन और मैक्सिको ने हर समय अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की आवश्यकता को भी दोहराया। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में निहित क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभु समानता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों का पालन करने पर भी जोर दिया। इतना ही नहीं उन्होंने

मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों और बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातचीत का मकसद मौजूदा हालात का कोई पक्का हल निकालना होना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि क्यूबा के लोग पूरी आजादी के साथ अपना भविष्य खुद तय करें। इसके साथ ही देश में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने कहा कि सौमित मात्रा में ईंधन की सप्लाई पहुंचाने की खबरों के बावजूद रूस से भेजी गई तेल की एक हालिया खेप को पिछले हफ्ते अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद बंदरगाह पर उतरने की इजाजत दी गई थी। देश में मानवीय जरूरतें अभी लगातार बनी हुई हैं। मार्च के आखिर से ऊर्जा संकट का अंतर और भी ज्यादा बिगड़ गया है। बता दें कि क्यूबा की ऊर्जा जरूरतें जनवरी में अमेरिका द्वारा राष्ट्रपति निकोलस माद्रुरो को सौंपे जाने तक बड़े पैमाने पर वेनेजुएला द्वारा पूरी की जाती थीं।

# उत्तर कोरिया ने दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, हाई अलर्ट पर जापान; दक्षिण कोरिया भी सतर्क

प्योंगयांग, एजेंसी। एशिया में एक बार फिर तनाव की लहर तेज हो गई है। रिविवा को दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने अपनी पूर्वी समुद्री सीमा की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब क्षेत्र पहले से ही सुरक्षा चुनौतियों और शक्ति संतुलन के दबाव से जूझ रहा है। लगातार हो रहे मिसाइल परीक्षण न केवल पड़ोसी देशों के लिए चिंता का कारण बन रहे हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अस्थिरता की आशंका को बढ़ा रहे हैं।

दक्षिण कोरियाई सेना के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अनुसार ये मिसाइलें रिविवा सुबह उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय इलाके सिनपो से छोड़ी गईं। यह इलाका पहले भी मिसाइल परीक्षणों के लिए जाना जाता रहा है। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वह इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और अपनी निगरानी व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है।

हाई अलर्ट पर जापान, देशभर में मंचा हड़कंप: इतना ही नहीं रिविवा सुबह जापान में उस समय हड़कंप मच गया, जब उत्तर कोरिया की ओर से कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की खबर सामने आई। स्थिति को भीभार मानते हुए जापान सरकार तुरंत हाई अलर्ट पर आ गई और देशभर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची ने बताया कि सुबह करीब 6



बजे उत्तर कोरिया की ओर से कई मिसाइलें छोड़ी गईं। हालांकि शुरुआती जानकारी के अनुसार ये मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर ही समुद्र में गिर गईं, जिससे किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है।

अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत जारी: इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस घटना के बाद जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया मिलकर स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं। सभी देश मिलकर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन मिसाइलों का मकसद क्या था और आगे क्या खतरा हो सकता है। घटना के तुरंत बाद जापान सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय के संकट प्रबंधन

केंद्र में एक आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि वे तैयारी से जागरूक जुटाएं और हर स्थिति के लिए तैयार रहें।

दक्षिण कोरिया ने बढ़ाई निगरानी: इस बीच दक्षिण कोरिया ने भी अपनी निगरानी बढ़ा दी है और वह लगातार अमेरिका और जापान के संपर्क में है। रिपोर्ट के मुताबिक, ये मिसाइलें उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय शहर सिनपो से दागी गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साल यह उत्तर कोरिया का सातवां बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण है और अप्रैल महीने में ही चौथा परीक्षण है। यह कदम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों

का उल्लंघन माना जा रहा है, क्योंकि इन नियमों के तहत उत्तर कोरिया को ऐसे परीक्षण करने की अनुमति नहीं है। हालांकि उत्तर कोरिया इन प्रतिबंधों को नहीं मानता और उसका कहना है कि यह उसके आत्मरक्षा के अधिकार के खिलाफ है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन पहले भी कह चुके हैं कि उनका देश अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु और मिसाइल ताकत को लगातार बढ़ाता रहेगा। इसी बीच, परमाणु मामलों की निगरानी करने वाली संस्था अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी चेतावनी दी है कि उत्तर कोरिया तेजी से अपनी परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है और उसने संभवतः यूरेनियम संकलन की नई सुविधा भी तैयार कर ली है।

## होमजु स्ट्रेट के दोबारा बंद होने से भड़का अमेरिका, ईरान के खिलाफ बनाई खास रणनीति

वाशिंगटन, एजेंसी। पश्चिम एशिया में जारी संकट अब और भी ज्यादा बढ़ने की कगार पर है। ईरान ने होमजु स्ट्रेट को दोबारा बंद कर दिया है। अब अमेरिका ने भी तेहरान के इस फैसले के खिलाफ ऐकेशन प्लान बना लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक ईरान के व्यापारिक जहाजों को केवल धमकी देने वाला अमेरिका अब होमजु से बाहर आने वाले और समुद्र में मौजूद जहाजों पर कब्जा करने की तैयारी में है। हालांकि, अभी तक अमेरिका की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के होमजु बंद करने के फैसले से नाराज अमेरिका अब ईरान के व्यापारिक जहाजों के ऊपर चढ़कर उन्हें जल करने की तैयार में है। दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से जर्नल ने बताया कि आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मौजूद ईरानी जहाजों को अमेरिका जल करना शुरू करेगा। इसके लिए वह होमजु के अलावा भी ऐकेशन लेने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन इस कदम के जरिए ईरान के ऊपर आर्थिक दबाव

बढ़ाना चाहता है। ताकि ईरान होमजु को खोलने और परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोकने के लिए मजबूर किया जा सके। बता दें, शुक्रवार को ईरान ने होमजु को खोलने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने होमजु के बाहर लगे ब्लाकेड को ईरानी जहाजों के लिए खोलने से इनकार कर दिया। इसके बाद ईरान ने ट्रंप के ऊपर वादा-खिलाफी का आरोप लगा, शनिवार को एक बार फिर से होमजु स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरानी सेना की तरफ से एक बयान जारी करके कहा गया कि ईरान ने लेबनान में सीजफायर को मजबूर रखते हुए होमजु को खोलने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों से निकलने वाले और यहां आने वाले जहाजों के लिए अपना ब्लाकेड नहीं खोला है। इसलिए अब इस्लामिक राज्य ईरान भी होमजु को दोबारा से बंद कर रहा है। ईरान ने इस घोषणा के बाद रेडियो के जरिए सभी जहाजों को होमजु के बंद होने की सूचना दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को होमजु के खोलने के ऐलान के साथ कई जहाज यहां से निकलने के लिए आगे बढ़े।

## कर्ज नहीं चुका पा रहा मालदीव, मुड़जू को आई भारत की याद: करेंसी स्वैपिंग की मांग रहे मदद

माले, एजेंसी। मालदीव में गहराते आर्थिक तनाव के बीच भारत सरकार मालदीव द्वारा करेंसी स्वैप सुविधा को विस्तार देने के अनुरोध पर विचार कर रही है। हालांकि, मौजूदा नियमों और सख्त शर्तों के कारण भारत के लिए इस अनुरोध को स्वीकार करना कूटनीतिक और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हो गया है। मालदीव वर्तमान में भारी अंतरराष्ट्रीय कर्ज और घटते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण गंभीर वित्तीय दबाव में है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने पर्यटन और ऊर्जा लागतों को प्रभावित कर मालदीव की कमाई और तोड़ दी है।

सूत्रों के मुताबिक, मालदीव ने भारत से फिर से करेंसी स्वैप सुविधा बढ़ाने की गुहार लगाई है। लेकिन भारतीय नियमों के अनुसार, दो बार निकासी के बीच एक क्लिंग-ऑफ (निश्चित



समय का अंतर) का होना अनिवार्य है। साथ ही रोल-ओवर (कर्ज की अवधि बढ़ाना) की भी एक तय सीमा होती है। इन तकनीकी कारणों से भारत के लिए दोबारा मदद देना आसान नहीं है। यदि भारत इस बार विस्तार नहीं दे पाता है, तो मालदीव की वित्तीय स्थिति अल्पावधि में और अधिक बिगड़ सकती है।

भारत का अब तक का सद्योग्य: भारत ने पिछले कुछ वर्षों में मालदीव की समस्याओं

को दूर करने के लिए कई असाधारण कदम उठाए हैं। अक्टूबर 2024 में भारत ने 400 मिलियन डॉलर की करेंसी स्वैप सुविधा प्रदान की थी, जिसे सख्त नियमों के बावजूद दो बार रोल-ओवर किया गया। मई और सितंबर 2025 में भारत ने 50-50 मिलियन डॉलर के दो ब्याज मुक्त ट्रेजरी बिलों की अवधि एक साल के लिए बढ़ा दी। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान बुनियादी ढांचे के लिए 565 मिलियन डॉलर की 'लाइव ऑफ क्रैडिट' और ऋण चुकाने की शर्तों में ढील देने की घोषणा की गई थी। नाजुक दौर में मालदीव की अर्थव्यवस्था रेटिंग एजेंसियों के अनुसार, मालदीव की स्थिति बेहद चिंताजनक है। फिच रेटिंग्स ने मालदीव की संवर्धन रेटिंग को 'सीसी' पर रखा है, जो कर्ज चूक

की उच्च संभावना को दर्शाता है। मुड़जू ने भी अपनी 'सोएट' रेटिंग बरकरार रखी है। अप्रैल 2026 में मालदीव को लगभग 1 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना था, जिसमें 500 मिलियन डॉलर का सुकुक बॉन्ड और भारत के साथ 400 मिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप शामिल है। 1 अप्रैल, 2026 में मालदीव सरकार ने अपने संवर्धन डेवलपमेंट फंड से सुकुक बॉन्ड का भुगतान तो कर दिया, लेकिन इससे उसका विदेशी मुद्रा भंडार काफी कम हो गया है। मालदीव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर टिकी है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है और ईरान की कमीतें बढ़ गई हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में मालदीव के लिए नए अंतरराष्ट्रीय ऋण जुटाना भी मुश्किल होता जा रहा है।

## 'ईरान वेनेजुएला नहीं है': गालिबाफ का बड़ा दावा- दुश्मन की हर योजना नाकाम

तेहरान, एजेंसी। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की लगभग सभी सैन्य योजनाएं पूरी तरह विफल हो गईं। उनका कहना है कि दुश्मन ईरान की एयरफोर्स और मिसाइल ताकत को कमजोर नहीं कर सका, न ही नौसेना को खत्म कर पाया और न ही जमीनी हमला सफल रहा। उन्होंने खास तौर पर यह भी कहा कि होमजु जलडमरूमध्य को खोलने या उस पर पूरी तरह नियंत्रण हासिल करने की कोशिश भी नाकाम रही।

विचौलियों के जरिए संदेश भेज रहे हैं ट्रंप: गालिबाफ ने कहा कि दुश्मन ने पहले चेतावनियां और समयसीमा देकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उसमें भी सफलता नहीं मिली तो अब वह 'विचौलियों के जरिए संदेश भेजने' लगा है। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने युद्ध के मैदान में बढ़त बनाई, जिसके कारण अस्थायी युद्धविराम हुआ। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि ट्रंप अपने लक्ष्य, ईरान में सत्ता परिवर्तन और उसकी सैन्य क्षमता जरूरतें, में पूरी तरह असफल रहे। गालिबाफ ने यह भी कहा कि 'ईरान वेनेजुएला नहीं है', यानी यहां बाहरी दबाव से सरकार नहीं बदली जा सकती।

ईरान ने अलग रणनीति अपनाकर मजबूत दुश्मन को पीछे धकेला: ईरानी संसद के अध्यक्ष ने माना कि सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका ईरान से ज्यादा मजबूत है, लेकिन उन्होंने



जोर देकर कहा कि सिर्फ हथियार, पैसा और संसाधन ही जीत तय नहीं करते। उनके मुताबिक, ईरान ने 'असिमेट्रिक वारफेयर' यानी अलग रणनीति अपनाकर मजबूत दुश्मन को पीछे धकेल दिया। इस बीच, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों पर समझ बनी है, लेकिन अभी भी कई बड़े मतभेद बाकी हैं। उन्होंने साफ कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा और कूटनीति में भी शुक्रने का सवाल नहीं उठता।

'अमेरिका फर्स्ट' दिखावा, इजाइल को प्राथमिकता देने का आरोप: मोहम्मद गालिबाफ ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका 'अमेरिका फर्स्ट' की बात करता है, लेकिन असल में वह इजाइल के हितों को प्राथमिकता देता है और उसी के आधार पर फैसले लेता है। हालांकि जमीनी स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। हाल के घटनाक्रम में होमजु जलडमरूमध्य को लेकर बार-बार स्थिति बदल रही है, कभी इसे खोलने की घोषणा होती है, तो कभी फिर से बंद करने की बात सामने आती है।



## गुजरात के उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ से हालात हुए बेकाबू, पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग

एजेंसी सूत्रों)। गर्मी की छुट्टियां, शादी का सीजन और फेवटारियों में छुट्टियां घोषित होते ही गुजरात के सूरत में रहने वाले प्रवासी मजदूर अपने-अपने घर लौटने के लिए बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशनों पर उमड़ पड़े हैं। इसी के चलते उधना रेलवे स्टेशन पर हालात बेकाबू हो गए। इसके चलते स्टेशन पर भादड़ जैसे दृश्य देखने को मिले। इससे निपटने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। यात्रियों की भारी भीड़ और ट्रेनों की कमी के कारण स्टेशन परिसर में हालात बेकाबू हो गए और अफरा तफरी मच गयी। यात्री रेलवे स्टेशन के बाहर 12 से 24 घंटे तक की कतारों में भूखे-प्यासे खड़े हुए हैं। धैर्य टूटने पर कई लोगों ने स्टेशन की बाउंड्री क्रूडकर अंदर घुसने की कोशिश की, जिससे हालात बेकाबू हो गए। इस स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा।

## पंच परिवर्तन से समाज में सकारात्मक बदलाव संभव : वी. सुरेंद्रन

पश्चिमी सिंहभूम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर आयोजित जन गोष्ठी में मुख्य अतिथि एवं भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री वी.सुरेंद्रन ने कहा कि 'पंच परिवर्तन' की अवधारणा के माध्यम से समाज में व्यापक और सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी और नारिकेल कर्तव्यों के पालन को राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव बताते हुए युवाओं से इसमें सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। चाईबासा के माध्यम सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हुए। अपने विस्तृत संबोधन में वी. सुरेंद्रन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संघ ने स्थापना काल से ही समाज को संगठित और सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। सेवा, समर्पण और संगठन के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, ग्राम विकास, स्वास्थ्यलंबन और आगढ़ प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में स्वयंसेवकों का योगदान उल्लेखनीय रहा है। संघ का शताब्दी वर्ष केवल उत्सव का अवसर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और समाज के प्रति अपने दायित्वों को और बेहतर तरीके से निभाने का समय है।

## बेटियों की हार में लोकतंत्र की जीत कैसे हो सकती है : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला आरक्षण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को लेकर लोकसभा में हुए घंटायाम में कड़ा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिनों में संसद में जो देखने को मिला, वह बेहद अफसोसजनक है और यह देश की महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय है। आजादी के 78 वर्षों बाद भी देश की बेटियां अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने उन दलों पर निशाना साधा जो 'लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ' का नारा देते रहे, लेकिन अब महिलाओं की इस लड़ाई से पीछे हट गए और इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि बेटियों की हार में लोकतंत्र की जीत कैसे हो सकती है? दिन दयाल उपध्याय मार्ग स्थित दिल्ली भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पिछले 30 वर्षों से बार-बार संसद में आता रहा है, लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने से उसे रोका गया। कभी फाड़ा गया, कभी दबाया गया, कभी जलाया गया। इस बार भी विपक्ष ने जानबूझकर विभिन्न तर्कों गढ़कर इसे पास नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 2023 में पारित विधेयक में साफ तौर पर लिखा है कि महिलाओं के लिए आरक्षण डिलिमिटेशन (परिसीमन) के बाद लागू होगा। ऐसे में आज उसी प्रवधान को लेकर विरोध करना विरोधाभासी है। जब 2023 में यही शर्त स्वीकार की गई थी तो आज विरोध किस बात का है?

## भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस और मुस्लिम समाज उत्तरदायी: नरेंद्र कश्यप

लखनऊ। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भारत विभाजन वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। यूपी सरकार में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कुमार कश्यप ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान देश के लिए सही नहीं है। यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप ने समाचार एजेंसी बात करते हुए कहा, "भारत का विभाजन हुआ, देश ने देखा और देश ने उस त्रासदी को भी झेला है। लाखों लोगों की मौत हुई। जिना और नेहरू इसके सूत्रधार थे। यदि मुस्लिम समाज के लोग चाहते, तो भारत का विभाजन नहीं होता। अभी भी देखते हैं न हम कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो देश में रहते हैं और देश के खिलाफ बोलते हैं। देश में रहते हैं, भारत माता के जय नहीं बोलते हैं। देश में रहते हैं, पाकिस्तान के मैच हारने पर मातम मनाते हैं। उस समय की परिस्थितियां इससे भी विकराल थीं। इसलिए कांग्रेस पार्टी और मुसलमानों को विभाजन का उत्तरदायी क्यों ना माना जाए? यह बात तो सही है, मानना पड़ेगा।" उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक पहचान देश में थी, दुनिया में भी इस बात को लेकर बनी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कहती है उसे करती है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अगर समान नारिकेल सहित लागू करने की बात कही है तो निश्चित है हमारी सरकार उसके प्रति प्रतिबद्ध है।

## महाकुंभ में वायरल हुई मांडल हर्षा रिछारिया ने लिया संन्यास, उज्जैन में खुद पिंडदान कर त्यागा पिछला जीवन

एजेंसी उज्जैन। प्रयागराज महाकुंभ में वायरल हुई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेन्ट क्रिएटर और पूर्व मांडल हर्षा रिछारिया ने अक्षय तृतीया के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में संन्यास ले लिया। उन्हें उज्जैन के मीनी तीर्थ आश्रम में पंचायती निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद गिरि महाराज ने संन्यास दीक्षा दी।

अक्षय तृतीया के अबूझ मुहूर्त में उज्जैन में मंगलनाथ स्थित गंगाघाट पर मौन तीर्थ पीठाधीश्वर सुमनाजी महाराज से विधि विधान से दीक्षा लेकर हर्षा रिछारिया को संन्यासी जीवन ग्रहण कराया। संन्यास परंपरा के अनुसार, उन्हें शिखा और दंड त्याग की विधि कराई गई। साथ ही तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म भी कराए गए, जो पूर्व जीवन के त्याग और नए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक माने जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद हर्षा रिछारिया ने संन्यास ग्रहण किया और उन्हें नया नाम स्वामी हर्षानंद गिरि दिया गया। इस



कहा कि यह उनके जीवन का नया अध्याय है। उन्होंने गुरुदेव के मार्गदर्शन में संन्यास का मार्ग अपनाया है और संकल्प लिया है कि वे अपना जीवन धर्म, संस्कृति और समाज की सेवा में समर्पित करेंगी और संन्यास की मर्यादा का पालन करेंगी। महामंडलेश्वर स्वामी

## महिला आरक्षण की राह में बाधा डालकर कांग्रेस और गठबंधन के दलों ने 'महापाप' किया है : विष्णुदेव साय

एजेंसी रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश की आधी आबादी को नेतृत्व के अधिकार से वंचित करने के उद्देश्य से महिला आरक्षण की राह में बाधा डालने का जो 'महापाप' कांग्रेस और गठबंधन के दलों ने किया है, उसका परिणाम उन्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री साय ने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, रायपुर महापौर मीनल चौबे, सांसद कमलेश जांगड़े, सांसद लक्ष्मी वर्मा के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लोक सभा में पारित नहीं हो पाने पर पत्रकारवार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लोक सभा में 131वें संविधान संशोधन महिला आरक्षण

बिल की राह में बाधा डालकर कांग्रेस, टीएमसी व सपा ने देश की 70 करोड़ महिलाओं के साथ विश्वासघात किया



है। आज पूरे विपक्ष का चेहरा उजागर हो चुका है। आने वाले समय में इंडी गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम सबका हमारा संघर्ष जारी रहेगा और महिलाओं को लोक सभा तथा विधान सभा में 33

प्रतिशत का हक दिलाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक हमारी माताओं-बहनों के लिए लोक सभा और विधान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करने वाला था। लेकिन, परिवारवादी राजनीति और वोट बैंक

## माफिया गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा : जी किशन रेड्डी

एजेंसी आसनसोल। केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने रानीगंज में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं में जोश भरा। स्पॉट्स असेंबली मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में उनका जोरदार स्वागत किया गया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत रानीगंज विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पार्थ घोष ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। इसके बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष शमशेर सिंह, दिनेश सोनी, बीएमएस के अखिल भारतीय सदस्य जयनाथ चौबे, आशा शर्मा और अपूर्व हजारा सहित अन्य नेताओं ने उनका अभिन्दन किया। कोयला क्षेत्र को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि माफिया गतिविधियों को किसी भी



बाद ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। अपने संबोधन में जी. किशन रेड्डी ने कार्यकर्ताओं को संगठन की बूथ स्तर पर मजबूत

करने का संदेश दिया और कहा कि चुनाव में जीत का आधार जमीनी

स्तर पर सक्रियता होती है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे घर-घर जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं और भाजपा प्रत्याशी पार्थ घोष की जीत सुनिश्चित करें।

## बंगाल में प्रोटोकॉल तोड़कर झालमुड़ी की दुकान पर पहुंचे पीएम मोदी, बच्चों को भी खिलाया

एजेंसी कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग और सहज अंदाज झालग्राम में देखने को मिला। चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद एसपीजी की भारी सुरक्षा तोड़ प्रोटोकॉल से बाहर निकल कर प्रधानमंत्री मोदी अचानक सड़क किनारे स्थित एक दुकान पर रुक गए। इस दौरान उन्होंने झालमुड़ी (चावल का भुजा जो तेल प्याज और मिर्ची मिलाकर बनाया जाता है) का स्वाद लिया, बच्चों और महिलाओं को खिलाया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की।

प्रधानमंत्री के अचानक रुकने से सुरक्षा व्यवस्था में तनाव कमी भी कुछ क्षणों के लिए चूँक गए, जबकि स्थानीय लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में कई चुनावी

दुकान पर पहुंचे और दुकानदार से झालमुड़ी बनाने को कहा। दुकानदार ने मुरमुरा, मसाला, मिर्च, तेल और अचार मिलाकर झालमुड़ी तैयार की। प्रधानमंत्री ने पहले वहां



मौजूद कुछ बच्चों को खिलाया, उसके बाद स्वयं भी झालमुड़ी खाई। इस दौरान आसपास मौजूद लोग जय श्री राम और नरेंद्र मोदी जित्दाबाद के नारे लगाते रहे। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें

प्रधानमंत्री लोगों के बीच सहज भाव से दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वह स्थानीय महिलाओं से बातचीत करते और हलचल पृष्ठे भी नजर आए। महिलाओं ने भी प्रधानमंत्री से मिलकर खुशी जताई। बताया जा रहा है कि जिस दुकान पर प्रधानमंत्री रुके, वह बिहार के गया जिले के विक्रम साह की है।

विक्रम साह पिछले 12 वर्षों से झालग्राम में झालमुड़ी की दुकान चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के आने की कोई पूर्व सूचना नहीं थी। अचानक काफिरा रुका और प्रधानमंत्री उनकी दुकान पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे अच्छी झालमुड़ी बनाने को कहा, जिसके बाद उन्होंने मसालेदार झालमुड़ी तैयार की। विक्रम साह ने बताया कि झालमुड़ी खाने के बाद प्रधानमंत्री ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि स्वाद बहुत अच्छा है।

## ओरछा के लिए पीएमश्री हेली सेवा के रूप में शुरू की गई है पुष्पक विमान सुविधा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

एजेंसी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ओरछा में राजा के रूप में विराजमान भगवान श्रीराम के दर्शन के लिए पीएमश्री हेली सेवा के रूप में पुष्पक विमान की सुविधा शुरू की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव राजधानी भोपाल के के स्टेट हैंगर से पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा के अंतर्गत नए सेक्टर 'भोपाल-चंदेरी-ओरछा' का शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परशुराम जयंती के मंगल अवसर पर पर्यटन की दिशा में आज मध्य प्रदेश ऐतिहासिक कदम बढ़ा रहा है। आज भोपाल-ओरछा और चंदेरी सेक्टर के लिए पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का शुभारंभ हो रहा है।

चंदेरी, पौराणिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन नगरी के रूप में विख्यात है। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे एविएशन सेक्टर से महाराष्ट्र सहित कई राज्य प्रेरणा ले रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यात्रियों को बोर्डिंग पास प्रदान किए और हेलीकॉप्टर को इंजी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश में पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को सुगम, सुरक्षित और आनंददायक बनाना हेली पर्यटन सेवा का उद्देश्य है। कार्यक्रम में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, भोपाल महापौर मालती राय

हट जाता है। सोनोवाल ने परिसीमन के मुद्दे पर भी बात करते हुए कहा कि देश की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए संसदीय क्षेत्रों का पुनर्गठन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज एक सांसद को औसतन 26 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करना पड़ रहा है, ऐसे में परिसीमन

एजेंसी मैसूर। कर्नाटक के मैसूर जिले के केआर नगर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें कावेरी नदी में डूबने से छह लोगों की मौत हो गई। यह घटना अर्केश्वर मंदिर के पास स्थित पुराने एडथोरे अर्केश्वर स्वामी मंदिर क्षेत्र में हुई। मुख्यमंत्री सिद्धार्थमैया ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है। यहां स्थित हजरत खादर लिंगबल्ली दरगाह में उस कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान आठ लोग कावेरी नदी में उतरे और तैरने का प्रयास किया, लेकिन नदी की तेज धारा और गहराई के कारण छह लोग पानी में फंस गए और बाहर नहीं निकल सके। स्थानीय लोगों ने तुरंत

## कावेरी नदी में डूबने से 6 लोगों की मौत, उर्स कार्यक्रम के दौरान हुआ हादसा

बचाव अभियान शुरू किया और दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घायलों को आगे के इलाज के लिए मैसूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान मैसूर के 5 वर्षीय उमर, बेंगलुरु की 13 वर्षीय ऐमन, केआर नगर के 13 वर्षीय अफ्रीफ, बेंगलुरु के 23 वर्षीय यासीन, बेंगलुरु की 22 वर्षीय नेहा और उटी की 30 वर्षीय फातिमा के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही केआर नगर पुलिस मोकै पर पहुंची और जॉंच शुरू कर दी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच जारी है। मुख्यमंत्री सिद्धार्थमैया ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपये प्रति परिवार के मुआवजे की घोषणा की।

## उतराखंड और पंजाब के राज्यपाल विश्व शांति सद्भावना सम्मेलन में हुए शामिल

एजेंसी नई दिल्ली। उतराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमोत सिंह (से नि) और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आज गुरुग्राम में अहिंसा विश्व भारती द्वारा जैन आचार्य लोकेश मुनि के जन्मोत्सव पर आयोजित 'विश्व शांति सद्भावना सम्मेलन' में भाग लिया। उन्होंने विश्व शांति और वैश्विक भाईचारे को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत आचार्य लोकेश के 66वें जन्म दिवस के पवन अवसर पर 'वी सपोर्ट पीथ' अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सीनियर सिटीजन केसरी क्लब की अध्यक्ष डॉ. किरण चोपड़ा तथा आचार्य पुंडरिक गोस्वामी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उतराखंड राज्यपाल ने कहा कि अहिंसा, करुणा, समानता और भाईचारा मानवता के विकास के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह

राज्यपाल ने कहा कि अहिंसा, करुणा, समानता और भाईचारा मानवता के विकास के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक महान संत की जयंती नहीं, बल्कि उनके बताए गए मूल्यों को याद करने का अवसर भी है, जो दुनिया में शांति और एकता लाने में मदद करते हैं। उतराखंड राज्यपाल ने कहा कि आज दुनिया कई समस्याओं जैसे अस्थिरता, पर्यावरण संकट और सामाजिक असमानता का सामना कर रही है। इन समस्याओं का समाधान केवल नीतियों से नहीं, बल्कि लोगों के अंदर बदलाव और अच्छे विचारों से ही संभव है। उन्होंने कहा कि सच्ची शांति अहिंसा, बातचीत और सहिष्णुता से आती है। उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा, अनेकतावाद और अपरिग्रह के संदेश को आज भी प्रासंगिक बताया। उन्होंने कहा कि अलग-अलग विचारों को समझने से आपसी मतभेद कम हो सकते हैं। उतराखंड राज्यपाल ने कहा कि भारत हमेशा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना को मानता आया है और दुनिया को एकता और भाईचारे का संदेश देता

## चारधाम यात्रा : अब तक 19.52 लाख से अधिक पंजीकरण

एजेंसी देहरादून। उतराखंड की चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह व आस्था देखी जा रही है। इस साल चारधाम के लिए अब तक कुल 19.52 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने विभिन्न धामों के लिए पंजीकरण कराया है। शाम पर्यटन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक केदारनाथ धाम के लिए सबसे अधिक 6.80 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है, जबकि बद्रीनाथ के लिए 5.75 लाख, गंगोत्री के लिए 3.43 लाख, यमुनोत्री के लिए 3.33 लाख और हेमकुंड साहिब के लिए करीब 19 हजार पंजीकरण दर्ज किए गए हैं। रिविचर से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। यात्रा के शुरुआती दिनों में ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के लिए

20 और 21 अप्रैल के लिए कुल 28,723 तीर्थयात्रियों का पंजीकरण कराया है। उतराखंड के विभिन्न पंजीकरण केंद्रों पर भी यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। केवल एक दिन में 3,698 श्रद्धालुओं ने



ऑफलाइन पंजीकरण कराया, जिसमें हरिद्वार और ऋषिकेश प्रमुख केंद्र हैं। सरकार की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1364 जारी किया गया है, जिससे यात्रा से जुड़ी जानकारी और सहायता प्राप्त की जा सकती है।

## नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कांग्रेस ने किया 'पाप', सजा भुगतनी होगी: सर्वांगद सोनोवाल

एजेंसी रांची। केंद्रीय मंत्री सर्वांगद सोनोवाल ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्ष ने जो रुख अपनाया है, वह महिलाओं के खिलाफ है

और इसके लिए उन्हें राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। रांची स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सोनोवाल ने कहा कि कांग्रेस की नीतियां हमेशा महिलाओं को सीमित दायरे में रखती रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के

लिए महिला नेतृत्व केवल इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तक ही सीमित है, जबकि अन्य महिलाओं को उचित स्थान नहीं दिया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने 'सेवक' के रूप में देश की सेवा की है और हर वर्ग

की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी पहल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कहा कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र

सरकार ने 33 प्रतिशत आरक्षण देने के उद्देश्य से विशेष सत्र बुलाया, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने इस प्रयास का विरोध कर महिलाओं का अपमान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का रवैया नारी समाज के प्रति अनादर दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि

भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के रहते देश में महिलाएं सुरक्षित हैं और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित है। उन्होंने विपक्ष पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब संवैधानिक अधिकार देने की बात आती है, तो विपक्ष पीछे

हट जाता है। सोनोवाल ने परिसीमन के मुद्दे पर भी बात करते हुए कहा कि देश की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए संसदीय क्षेत्रों का पुनर्गठन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज एक सांसद को औसतन 26 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करना पड़ रहा है, ऐसे में परिसीमन

समय की मांग है। उन्होंने झारखंड सरकार की 'मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना' को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि जब केवल दिखावटी योजना है, जबकि केंद्र सरकार महिलाओं की वास्तविक भागीदारी बढ़ाने के लिए काम कर रही है।



## ‘आप पर्दे पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, असल में नहीं’



प्रकाश राज ने ‘जन नायकन’ को एक्टर थलापति विजय पर कसा तंज

अभिनेता प्रकाश राज अपने बेबाक बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वो अक्सर ही केंद्र सरकार पर निशाना भी साधते रहते हैं। अब प्रकाश राज ने ‘जन नायकन’ के अपने को-एक्टर थलापति विजय के राजनीति में प्रवेश करने पर कटाक्ष किया है। विजय अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलना वेट्टी कजगम (टीवीके) के साथ आगामी तमिलनाडु चुनावों के प्रचार में व्यस्त हैं। ऐसे में प्रकाश राज ने राजनीति के सिनेमा मॉडल पर निशाना साधा है।

प्रकाश राज ने राजनीति में फिल्मी सितारों के आने पर कसा तंज

पलानी में सीपीआई (एम) उम्मीदवार एन पांडी के लिए आयोजित एक प्रचार कार्यक्रम में बोलते हुए प्रकाश राज ने राज्य में प्रचलित तीन राजनीतिक दृष्टिकोणों का उल्लेख किया - द्रविड़ मॉडल, दास मॉडल और सिनेमा मॉडल। सभा को संबोधित करते हुए प्रकाश राज ने फिल्म सितारों के राजनीति में आने की बढ़ती प्रवृत्ति पर सवाल उठाया, जो स्पष्ट रूप से विजय की ओर इशारा था।



कहा- अभी-अभी बच्चे को जन्म दिया है

## मां बनने के बाद बढ़ते वजन पर ट्रोल करने वालों को भड़कीं पत्रलेखा

सोशल मीडिया की दुनिया जितनी तेज और चमकदार दिखती है, उतनी ही तनावपूर्ण भी होती है। खासकर फिल्मी सितारों के लिए यह दबाव और भी बढ़ जाता है, जहां हर बदलाव के साथ यूजर्स के कमेंट्स से गुजरना पड़ता है। इस कड़ी में अभिनेत्री पत्रलेखा को भी ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। मां बनने के बाद उनके बढ़ते वजन को लेकर लोग लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। इस पर पत्रलेखा ने ट्रोलर्स को करार जवाब दिया। पत्रलेखा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें अभिनेत्री ने कहा कि उन्होंने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है और यह उनके शरीर में आए बदलाव का सबसे बड़ा कारण है। पत्रलेखा ने उन लोगों को निशाने पर लिया, जो लगातार उनके बढ़ते हुए वजन पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ‘मुझे क्या हुआ है, इसका जवाब यही है कि मैंने अभी-अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। यह बदलाव पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लोनों को ऐसा लगता है जैसे मैंने जल्द से जल्द खा लिया हो, जबकि सच्चाई यह है कि मैंने इस दौरान एक नई जिंदगी को जन्म दिया है।’ पत्रलेखा ने कहा, ‘प्रेग्नेंसी के दौरान और उसके बाद

शरीर में बदलाव आना पूरी तरह सामान्य बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग बिना समझे तुरंत कमेंट कर देते हैं। मैंने पहाड़ नहीं खया है, बल्कि एक बच्चे को जन्म दिया है। मैं अपनी मातृत्व की जिम्मेदारी निभा रही हूँ और साथ ही दो फिल्मों के निर्माण का काम भी संभाल रही हूँ, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है।’

पत्रलेखा

ने उन लोगों को निशाने पर लिया, जो लगातार उनके बढ़ते हुए वजन पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ‘मुझे क्या हुआ है, इसका जवाब यही है कि मैंने अभी-अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। यह बदलाव पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लोनों को ऐसा लगता है जैसे मैंने जल्द से जल्द खा लिया हो, जबकि सच्चाई यह है कि मैंने इस दौरान एक नई जिंदगी को जन्म दिया है।’ पत्रलेखा ने कहा, ‘प्रेग्नेंसी के दौरान और उसके बाद

अपने पोस्ट के आखिर में पत्रलेखा ने लोगों से भावनात्मक अपील की और कहा, ‘आर मेरे हाथ में होता तो मेरा शरीर ऐसा न होता, लेकिन यह पूरी तरह शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। मेरी लोनों से आग्रह किया कि किसी भी महिला के शरीर पर कमेंट करने से पहले उसके हालात और संघर्ष को समझने की कोशिश करें। हर किसी को थोड़ा तो दयालु बनना चाहिए। पत्रलेखा और अभिनेता राजकुमार राव ने पिछले साल 15 नवंबर को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था। कपल ने अपनी बेटी का नाम पार्वती पॉल राव रखा।



## ‘कमर्शियल एक्टर्स’ पर ऋचा चड्ढा ने उठाए सवाल

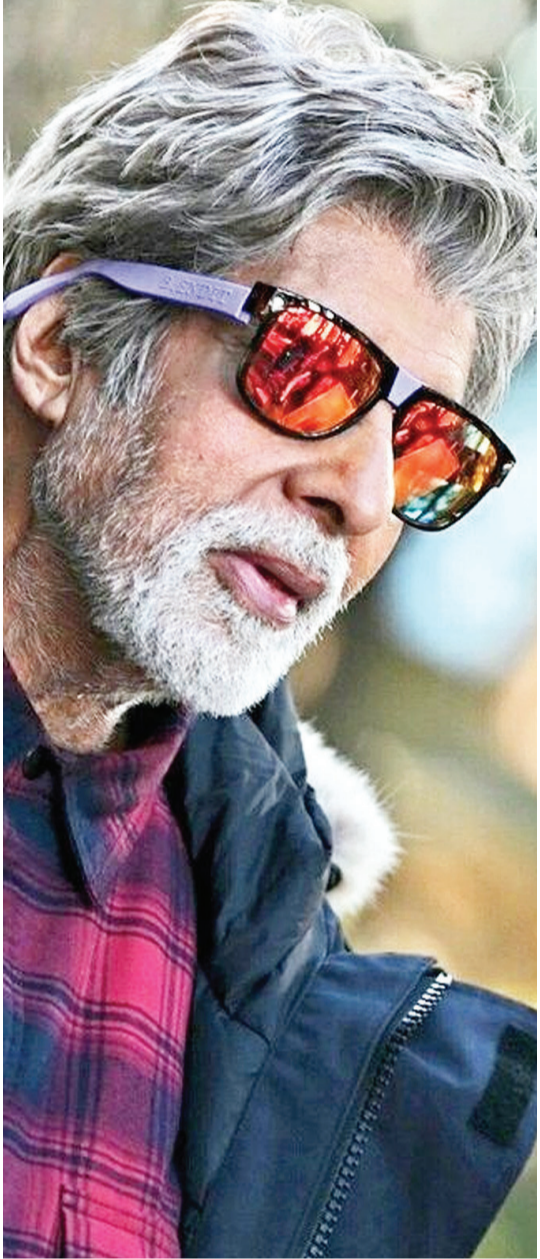
एक्ट्रेस-प्रोड्यूसर ऋचा चड्ढा अक्सर खुलकर कई मुद्दों पर बात करती और अपनी राय रखती नजर आती हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सवाल उठाया है कि इंस्टाग्राम फिल्ममेकर्स लगातार ‘कमर्शियल’ एक्टर्स को क्यों कास्ट करते हैं? उनका कहना है कि ऐसे एक्टर्स उन कहानियों के लिए न तो बॉक्स-ऑफिस तक दर्शकों को ला पाते हैं और न ही इंटी फिल्म को फेस्टिवल में कोई साख दिला पाते हैं। ऋचा ने एक बयान में कहा, ‘आगर कोई एक्टर शुक्रवार को आपकी फिल्म को थिएटर में ओपनिंग नहीं दिला पाता और न ही फेस्टिवल में कोई खास वजन जोड़ पाता है, तो फिर एक इंस्टाग्राम फिल्म में उसे कास्ट करने का आखिर फायदा क्या है?’

एक्ट्रेस ने कहा कि वह किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रही हैं, लेकिन ‘कम से कम ट्रेड एक्टर्स के साथ आपको यह धरोसा रहता है कि उनकी परफॉर्मेंस की क्वालिटी बनी रहेगी। इंटी फिल्मों के पीछे भी कमर्शियल सोच होती है, कुछ कहानियों को भीड़ खींचने के लिए हमेशा इतने बड़े चेहरों की जरूरत नहीं होती। ऐसे एक्टर को हायर करना ज्यादा फायदेमंद होता है जो कम बजट में भी फिल्म को साख दिला सके।’ उन्होंने आगे कहा, ‘किसी भी एक्टर की क्वालिटी या अहमियत को कम न करते हुए, मेरा मकसद यह है कि अगर इंटी फिल्मों को 2026 में संचय टिके रहना है, तो हमें यह समझना और सीखना होगा कि दर्शक अच्छी कहानियां देखना चाहते हैं, ऐसे क्वालिटी एक्टर्स के साथ जो बजट पर भारी न पड़ें, क्योंकि उनके साथ आने वाले लोगों का खर्च भी तो उठाना पड़ता है। ऋचा ने इस बात पर जोर दिया कि इंस्टाग्राम सिनेमा की बुनियाद हमेशा से ही रिस्क लेने, असलियत और मजबूत कहानियों पर टिकी रही है।



## मां के लिए जरीन खान का छलका दर्द, नोट शेयर कर लिखा, ‘आपके बिना सब खाली है’

अभिनेत्री जरीन खान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कुछ दिन पहले उनकी मां परवीन खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। शुक्रवार को अभिनेत्री ने अपनी मां के लिए खास पोस्ट किया। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर अपनी मां के साथ पुरानी यादों का मॉटाज वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में जरीन और उनकी मां साथ में हंसती-खेलती नजर आ रही हैं। जरीन ने पोस्ट में लिखा, ‘निश्चय ही हम ऊपरवाले के हैं और एक दिन हमें वहीं जाना है। मां, आपको गए हुए अभी बस 10 दिन हुए हैं। मैं दुनिया के लिए कोई बड़ा कैप्शन नहीं लिखूंगी, क्योंकि आप पहले से ही जानती हैं कि मैं अभी क्या महसूस कर रही हूँ। उन्होंने आगे लिखा, ‘मेरे दिल में एक दर्द और खालीपन है, जिसे कोई भी भर नहीं सकता। आप हमेशा सही रहें और ऊपर अच्छे से रहें, जब तक हम परसे नहीं मिलते हैं।’ अभिनेत्री जरीन खान की मां लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं। अक्टूबर 2025 में भी उनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभिनेत्री ने मां के स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था और लगातार अपडेट दे रही थीं। इसके साथ ही, फैंस से उनकी जल्दी ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ करने की अपील कर रही थीं। जरीन खान अपनी मां के बहुत करीब थीं और अक्सर सोशल मीडिया पर उनके साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती थीं। जरीन खान ने 2010 में सलमान खान के साथ फिल्म ‘वीर’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। कटरीना कैफ से समानता के कारण चर्चा में आई जरीन ने ‘हाउसफुल 2’, ‘हेट स्टोरी 3’ और ‘अक्सर 2’ जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें मुख्य रूप से ग्लैमरस भूमिकाओं के लिए जाना जाता है।



## ‘समय जल्दी बीत जाता है...’, अमिताभ बच्चन ने क्यों कही ये बात? पिता हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का किया जिक्र

सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन 83 साल की उम्र में भी फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया और ब्लॉग पर भी लगातार सक्रिय हैं। वो अक्सर अपने ब्लॉग के जरिए भी लोगों को प्रेरित करते रहते हैं और प्रेरणादायक बातें साझा करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने ब्लॉग पोस्ट में सक्रिय और प्रेरित रहने के महत्व पर विचार व्यक्त किया। इसके लिए उन्होंने अपने पिता व रचनाकार हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियों का भी जिक्र किया।

शरीर को गतिशील रखें

अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं से प्रेरणा लेते हुए अमिताभ ने समय की अस्थिरता और शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्रिय रहने के महत्व के बारे में बात की। अपने ब्लॉग में उन्होंने लिखा, ‘बाबूजी की रचनाओं से कुछ विचार और दिन बीतते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बीता था और अगला महीना शुरू होने वाला है। यह हमें याद दिलाता है कि समय कितनी जल्दी बीत जाता है। गतिशीलता ही कुंजी है। शरीर को गतिशील रखें, मन को गतिशील रखें और गतिशीलता की शक्ति अचानक स्पष्ट हो जाएगी, न कि बिना किसी कारण के बैठे रहने से।’

धैर्य और ज्ञान का बताया महत्व

बिग बी ने धैर्य और ज्ञान के महत्व पर भी बात की। उन्होंने लिखा, ‘धैर्य उस पहली की तरह है, जिसका हल हर पल चाहिए। एक पल भी धैर्य की परीक्षा है। लेकिन इसका फल मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है। आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि दार्शनिक दृष्टि से।’ उन्होंने ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, ‘किसी भी विषय का अध्ययन युद्ध के संदर्भ में धनुष से कई तीर निकालने जैसा है।



भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल इन दिनों मैदान से ज्यादा सोशल मीडिया पर छाप हुए हैं। इंफ्लुएंसर तान्या चटर्जी ने दावा किया था कि चहल ने उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था। इस छूटे से मैसेज ने देखते ही देखते बड़ा विवाद खड़ा कर दिया और इंटरनेट पर बहस छिड़ गई। इंफ्लुएंसर ने बातचीत में इस विषय पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ‘वह बस एक सामान्य मैसेज था। इसमें कोई बुराई या फिर विवाद छेड़ने जैसा कुछ भी नहीं था। मेरे मन में उनके लिए बहुत

इज्जत है। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। वे एक भारतीय खिलाड़ी हैं और देश के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने मुझे सिर्फ ‘क्यूट’ कहा था और आईपीएल के बारे में बातचीत चल रही थी। तान्या ने आगे बताया कि पूरी बातचीत के दौरान चहल से जुड़ा टॉपिक सामने आया और उन्होंने इसे ऐसे ही बता दिया। उन्होंने कहा, ‘मेरा इरादा चहल को बदनाम करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इसी तरह रहती हूँ। मुझमें वह मासूमियत

अभी भी है। मेरे अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा और हमेशा बरकरार रहेगा। उन्होंने मेरी तारीफ की थी, मुझे अच्छा लगा, बात खत्म।’ अभिनेत्री ने आगे कहा, ‘मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मानहानि का केस कैसे हो सकता है। मैंने तो उन्हें बदनाम नहीं किया, बल्कि, उनकी तारीफ ही की थी।’ उन्होंने कहा, ‘चहल एक भारतीय क्रिकेटर हैं और आईपीएल में खेल रहे हैं। मैं उनकी निजी जिंदगी में दखल नहीं दे रही हूँ और न ही किसी और चीज में। यह बस एक तारीफ थी, जिसे मैंने अपनी मासूमियत से सभी के सामने शेयर किया।’ तान्या ने अपनी बात को साफ करते हुए कहा कि यह घटना 2023 की है। अगर उन्हें कुछ ऐसा करना होता, तो वे पहले ही कर देती। यह 2023 में हुआ था। सबको पता था कि उस समय वह शादीशुदा थे। उन्होंने मुझे मैसेज किया था, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। मुझे यह दर से पता चला। लेकिन अगर मैं उस समय किसी पीआर या ऐसी ही किसी टीम के साथ जुड़ी होती, तो शायद मुझे पता चल जाता।

मेरा कोई पीआर नहीं है। इंफ्लुएंसर ने कहा कि मेरे वकील इस मामले को देख रहे हैं और उन्होंने मुझे ज्यादा कुछ कहने से मना किया है, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि उन्होंने ही मुझे मैसेज किया था। वह एक प्यारा सा मैसेज था और एक बार नहीं, दो बार किया था।

# अगले साल रिलीज होगी ‘लव एंड वॉर’

भंसाली की प्रेम कहानी में दिखेंगे रणबीर, आलिया और विक्की कौशल

बॉलीवुड में जब भी बड़े पैमाने की फिल्मों की बात होती है, तो संजय लीला भंसाली का नाम अपने आप सामने आ जाता है। अब एक बार फिर वह दर्शकों के लिए एक बड़ी और खास फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है ‘लव एंड वॉर’... इस फिल्म को लेकर पहले से ही काफी चर्चा हो रही है। इसकी रिलीज डेट सामने आने के बाद दर्शकों का उत्साह और बढ़ गया है। फिल्म की स्टार कास्ट काफी दमदार है। इसमें रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट जैसे बड़े



कलाकार नजर आएंगे। इस बीच मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया है। दरअसल, मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा कर इसकी रिलीज डेट की घोषणा की। इस तस्वीर में संजय लीला भंसाली के साथ रणबीर, विक्की और आलिया नजर आ रहे हैं। मेकर्स ने बताया कि यह फिल्म अगले साल गणतंत्र दिवस से पहले आएगी। यह फिल्म 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ‘लव एंड वॉर’ एक प्रेम

कहानी है। साथ ही इसमें भावनाओं और संघर्ष से भरे सीन्स भी देखने को मिलेंगे। यह फिल्म खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें भंसाली पहली बार विक्की कौशल के साथ काम कर रहे हैं।

वहीं, रणबीर के साथ उनकी ये दूसरी फिल्म है, इससे पहले वह फिल्म ‘सावरिया’ में उनके साथ काम कर चुके हैं। इसके अलावा, आलिया भट्ट के साथ वह ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ के बाद फिर से काम कर रहे हैं। ‘लव एंड वॉर’ की रिलीज डेट को लेकर चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि उसी समय कुछ और बड़ी फिल्मों के आने की संभावना है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।

## ग्रीस के एथेंस में स्थित है द पार्थेनॉन

इस भव्य मंदिर का निर्माण 447 ईसा पूर्व किया गया था। यह मंदिर एथेना देवी को समर्पित है। इस देवी को एथेंस के लोगों की संरक्षक माना जाता था। इस प्राचीन बिल्डिंग को 17 वीं शताब्दी में एक युद्ध के दौरान काफी नुकसान पहुंचा था। ग्रीस ने इसे सुरक्षित बनाए रखने के लिए काफी पैसा खर्च किया है। यह प्राचीन बिल्डिंग भूकंप के खतरे वाले इलाके में स्थित है।



## हजारों साल पुरानी इन बिल्डिंगों को देखकर इंजीनियर हो जाएंगे शर्मिदा!

आज आधुनिक तकनीक और श्रेष्ठ निर्माण सामग्री के बावजूद भी बेहद मजबूत बिल्डिंगों का निर्माण करना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन प्राचीन समय में कई ऐसी बिल्डिंग्स तैयार की गई थीं, जो सदियों बीतने के बावजूद आज भी मजबूती के साथ सुरक्षित खड़ी हैं। आज के इंजीनियर भी इन हजारों साल पुरानी बिल्डिंगों को बनाने वाले विशेषज्ञों की भवन निर्माण के ज्ञान के सामने स्वयं को बीना महसूस करते हैं। हालांकि उस समय आज की तकनीक, संसाधन और बेहतर निर्माण सामग्री उपलब्ध नहीं थी। ये बिल्डिंग्स न केवल प्राचीन ढांचा हैं, बल्कि लाखों लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई हैं। विश्व की कुछ ऐसे ही प्राचीन निर्माण के नमूनों को हम यहां देखेंगे।

### सांची का स्तूप

भारत के मध्य राज्य की राजधानी भोपाल के समीप रायसेन जिले में सांची में इस स्तूप का निर्माण तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने तैयार करवाया था। इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। यह दुनिया की प्राचीन सुरक्षित निर्माण कार्य में से एक है।



### इंडोनेशिया के मैगेलंग का बोरोबुदुर मंदिर

इस मंदिर को दुनिया की सबसे विशाल बौद्धिस्ट ऑर्केलॉजिकल साइट माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 9 वीं शताब्दी में किया गया था। इस मंदिर तक ऊंची चढ़ाई पैदल तय करना होती है।



### इटली के रोम का कैसल सेंट एंजेलो

एक समय यह रोम की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। शुरुआत में इसे रोमन सम्राट हैड्रियन के मकबरा के लिए बनाया गया था। इसका निर्माण ईशवी शताब्दी 117 में शुरू हुआ था और 138 में पूरा हुआ। अब यह एक नेशनल म्यूजियम है।



### तिब्बत के ल्हासा का जोखांग मंदिर

इस बौद्ध मंदिर का निर्माण 7 वीं शताब्दी में किया गया था। यह स्थान तिब्बतियों के सबसे पवित्र स्थानों में से प्रमुख है।



### जर्मनी के ट्रियर में स्थित द पोर्टा निग्रा

जर्मनी में द पोर्टा निग्रा का निर्माण 186 से 200 ईस्वी में हुआ था। इसे सैंड स्टोन से बनाया गया है। यह रोमन साम्राज्य की एक विशाल ऐतिहासिक धरोहर है। इसका नाम भी मध्ययुग में इसके काले पत्थरों रंग पर पड़ा है। इसका पहले का नाम अज्ञात है।



### इजिप्ट के सक्कारा में डिजोसेर पिरामिड

प्राचीन मिस्र की धरोहर सक्कारा नेक्रोपॉलिस में स्थित है। इसे 27 वीं ईपू में तैयार किया गया था। इस मिस्र के राजाओं को दफनाने के लिए बनाया गया था।

उंचाई - 62 मीटर (203 फीट), आधार - अधिकतम-125.27 मीटर (411 फीट), न्यूनतम - 109.12 मीटर (358 फीट)

### आयरलैंड के काउंटी मैथ का न्यूग्रेंज

इसका निर्माण आज से 5,000 साल पहले हुआ था। इसके अंदर चेंबर बने हुए हैं, जिनमें सूरज की रोशनी सीधे पहुंच सकती है। हर 100 लॉटरी विजेता ही इसके अंदर जाकर यहां का अनुभव ले सकते हैं।



## छोटी-सी बात के लिए हो गई बड़ी लड़ाई

युद्ध बहुत सी चीजों के लिए लड़े गए हैं। यह सम्मान, गौरव, आजादी जैसे कारणों के लिए उचित हो सकता है। लेकिन इतिहास में ऐसे भी कई युद्ध लड़े गए हैं, जिनके पीछे बहुत ही तुच्छ या छोटे कारण रहे हैं। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि कभी एक कुत्ते-बिल्ली जैसे जानवरों के कारण भी युद्ध लड़े गए हैं।

हम आपको यहां कुछ ऐसे ही युद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके पीछे कारण तो बहुत छोटे और विचित्र थे, लेकिन इसके बावजूद भी युद्ध हो गए। वॉर से कभी भी मानव जाति का भला नहीं हुआ है। विचित्र कारणों से लड़े गए वॉर के बारे में आप यहां जानेंगे। अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएं 1812 में मैने बार्डर के विवाद को लेकर अरोस्टुट का वॉर लड़ चुकी थीं। इसमें ब्रिटेन की सेना ने मैने के पूर्वी इलाके में कब्जा कर लिया था, लेकिन यहां कोई भी सैनिक तैनात नहीं थे। इस इलाके को आज भी ब्रिटिश सीमा के अंतर्गत माना जाता है। 1838 के सर्दियों के मौसम में अमेरिका के कुछ लकड़ी काटने वालों ने जलाऊ लकड़ी काट ली। इससे ब्रिटेन नाराज हो गया और उसने अपने सैनिक इस इलाके में भेज दिए। दूसरी ओर से अमेरिकी सैनिक भी आगे बढ़े और लगने लगा कि युद्ध संभावित है।



इस दौरान भूलवश अमेरिकी सैनिकों को सुअर का मांस और सेम के बीज बड़ी मात्रा में पहुंचा दिए गए। युद्ध के इंतजार में दोनों ओर की सेनाएं लंबे समय तक खड़ी रहीं, लेकिन युद्ध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारों के बीच एक समझौता हो गया। बीमारियों और दुर्घटनाओं में दोनों पक्षों के 550 से अधिक सैनिकों की मौत हो गई। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने दिसंबर 1838 से नवंबर 1839 तक डटी रहीं।

ग्रीस और बुल्गारिया के बीच शत्रुता थी और दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रथम विश्वयुद्ध में लड़ चुके थे। दोनों देशों के बीच 22 अक्टूबर 1925 को सीमावर्ती इलाके पेट्रिक में तनाव इसलिए बढ़ गया जब एक ग्रीक सैनिक ने अपने कुत्ते का पीछा बुल्गारिया सीमा तक किया और एक बुल्गारियन ने कुत्ते को गोली मार दी। ग्रीस ने अगले दिन बुल्गारिया की सेना को वहां से खदेड़ दिया। दस दिन तक चली इस लड़ाई में दोनों पक्षों के 42 सैनिक मारे गए। लीग ऑफ नेशंस ने बुल्गारिया पर 45,000 पाउंड का जुर्माना किया।

पैराग्वे वॉर - पैराग्वे का राष्ट्रपति फ्रांसिस्को सोलानो लोपेज नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत बड़ा प्रशंसक था और वह अपने आपको बड़ा कुशल कमांडर मानता था। उसने अपनी सैन्य कुशलता दिखाने के लिए ही 1864 में अपने तीन पड़ोसी देशों अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे पर हमला कर दिया। यह युद्ध छह साल तक चला और 1870 में खत्म हुआ। युद्ध में पैराग्वे की 90 फीसदी पुरुष आबादी नष्ट हो गई। इसमें दोनों पक्षों से 4,00,000 से अधिक मौतें हुईं। इतिहास का यह सबसे गैर जरूरी युद्ध माना जाता है, जो बिना किसी कारण के लड़ा गया था। लकड़ी की बॉल्टियों के लिए युद्ध - यह युद्ध 1325 में दो स्वतंत्र राज्यों मोडेना और बोलीगना के बीच महज लकड़ी से बनी बॉल्टी के लिए हुआ था। मोडेना के सैनिकों ने बोलीगना में एक जगह छपा मारा और लकड़ी से बनी बॉल्टियां चुराकर ले गए। बोलीगना ने अपने स्वाभिमान बॉल्टी वापस लाने के लिए मोडेना के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध 12 साल चला लेकिन वह बॉल्टी वापस नहीं ला सका। आज भी यह मोडेना के बेल टॉवर में बॉल्टियां रखी हुई हैं।

लिज्जार बनाम फ्रांस - 1883 में दक्षिण स्पेन में स्थित कस्बे लिज्जार के लोगों ने जब यह सुना के पेरिस में घूमने गए स्पेन के राजा अलफांसो अष्टम के साथ पेरिस के लोगों की भीड़ ने न केवल बदसलूकी की है बल्कि हमला भी बोला है। इससे नाराज लिज्जार के मेयर और 300 नागरिकों ने 14 अक्टूबर 1883 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन इसके बाद एक भी गोली नहीं चली, किसी की मौत नहीं हुई।

93 साल बाद 1976 में जब स्पेन के किंग जुआन-कार्लोस ने पेरिस की यात्रा की तो वहां के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इससे लिज्जार टाउन के स्थानीय प्रशासन ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा वापस ले ली।

पिग वॉर - अमेरिका और ब्रिटेन के बीच पिग वार (सुअर युद्ध) जून 1859 में हुआ और इसी साल अक्टूबर में खत्म हो गया। यह लड़ाई कुछ यूँ शुरू हुई कि एक ब्रिटिश सैनिक ने अमेरिका की जमीन पर घूम रहे सुअर को गोली मार दी। अमेरिकी मिलिशिया ने ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ने को खड़े हो गए और उनका इंतजार करने लगे। आखिर ब्रिटिश आर्मी के जवानों अपनी हरकत पर माफी मांग ली और सिवाय एक सुअर के किसी भी सैनिक की जान नहीं गई।

335 साल का युद्ध - यह युद्ध नीदरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के साउथवेस्ट समुद्री तट पर स्थित इसेल ऑफ सिसली के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 1651 में शुरू हुआ लेकिन इस अधिक गंभीरता से नहीं लिया गया और जल्द भुला दिया गया। तीन शताब्दी बाद दो देशों के बीच 1986 में एक शांति समझौता हुआ लेकिन यह मानव इतिहास का सबसे लंबा युद्ध गिना जाता है। लेकिन एक भी मौत नहीं हुई। युद्ध की अवधि - (1651-1986) तीन सौ पैंतीस वर्ष।

